ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

चतुर्थ अंक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
निर्णय पत्रिका

की प्रस्तुति

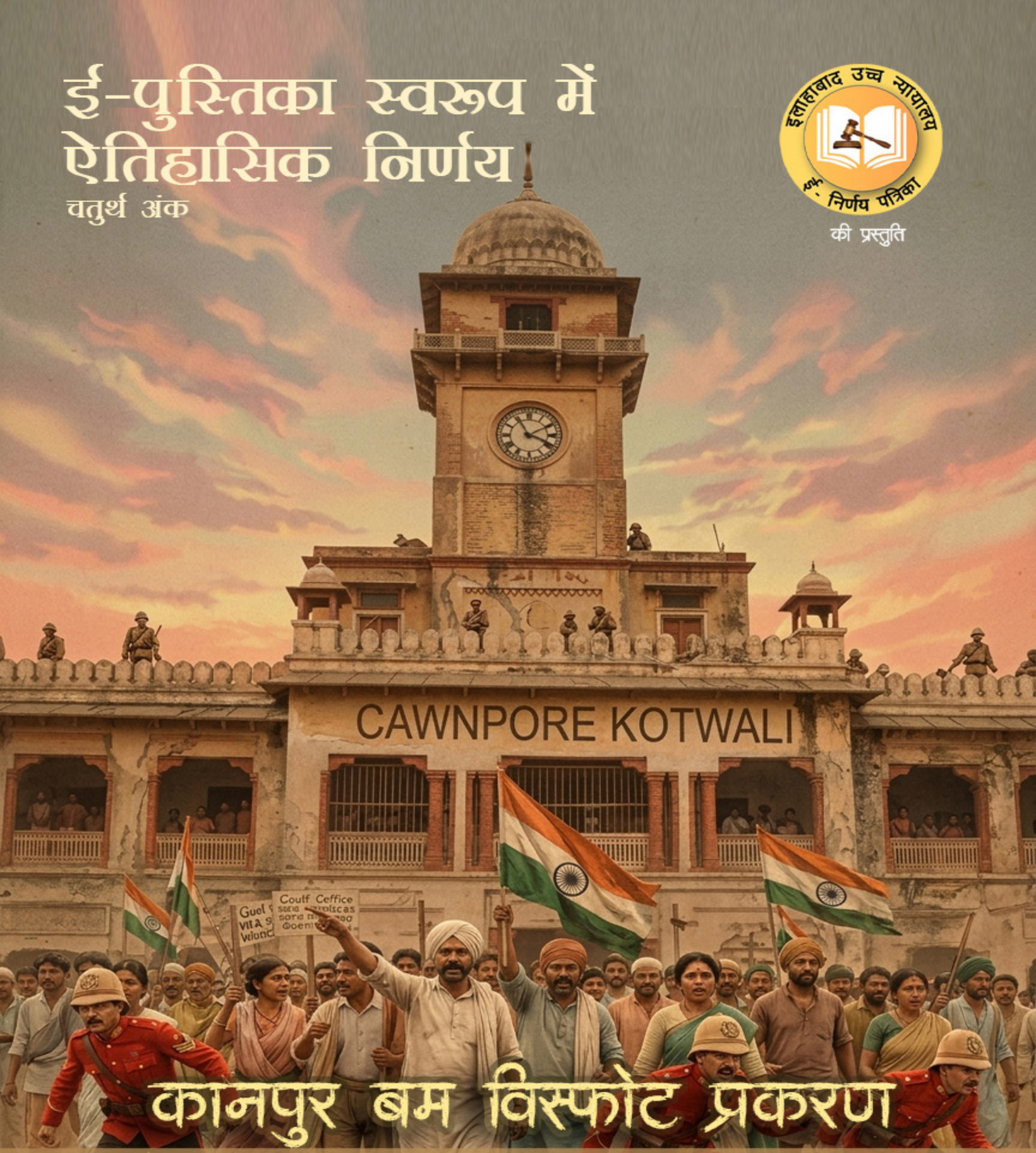

कानपुर बम विस्फोट प्रकरण

आपराधिक अपील संख्या 1028 सन् 1944 में पारित आदेश दिनांक 15/03/1946 (हिन्दी में अनुवादित)

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एप्वसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित

सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है

ऐ शहीद-ए-मुल्क-ओ-मिल्लत मैं तिरे ऊपर निसार
ले तिरी हिम्मत का चर्चा ग़ैर की महफ़िल में है

वाए क़िस्मत पाँव की ऐ ज़ोफ़ कुछ चलती नहीं
कारवाँ अपना अभी तक पहली ही मंज़िल में है

रहरव-ए-राह-ए-मोहब्बत रह न जाना राह में
लज़्ज़त-ए-सहरा-नवर्दी दूरी-ए-मंज़िल में है

शौक़ से राह-ए-मोहब्बत की मुसीबत झेल ले
इक ख़ुशी का राज़ पिन्हाँ जादा-ए-मंज़िल में है

आज फिर मक़्तल में क़ातिल कह रहा है बार बार
आएँ वो शौक़-ए-शहादत जिन के जिन के दिल में है

मरने वालो आओ अब गर्दन कटाओ शौक़ से
ये ग़नीमत वक़्त है ख़ंजर कफ़-ए-क़ातिल में है

माने-ए-इज़हार तुम को है हया, हम को अदब
कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है

मय-कदा सुनसान ख़ुम उल्टे पड़े हैं जाम चूर
सर-निगूँ बैठा है साक़ी जो तिरी महफ़िल में है

वक़्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमाँ
हम अभी से क्यूँ बताएँ क्या हमारे दिल में है

अब न अगले वलवले हैं और न वो अरमाँ की भीड़
सिर्फ़ मिट जाने की इक हसरत दिल-ए-'बिस्मिल' में है

- ख़ालिक़ बिस्मल अज़ीमाबादी

हमें अत्यंत गर्व है कि आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक “कानपुर बम विस्फोट प्रकरण” में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.3.1946 के अनुवाद पर आधारित ई-पुस्तिका के विमोचन के साक्षी बन रहे हैं, जो 'ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय' का चतुर्थ संस्करण है। यह प्रकरण 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के तत्काल बाद की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। कानपुर, जो उस समय एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का एक मुख्य गढ़ बन गया था। इस मामले में कुल 13 मुख्य अभियुक्तों पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, अवैध हथियारों के निर्माण, और सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे जिसमे अलग अलग दंड लगाए गए।

"कानपुर बम विस्फोट प्रकरण” भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर है और इसे हम जनमानस के लिए विनम्रतापूर्वक लोकार्पित करते है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी द्वारा संकल्पित यह संस्करण विधिक शोधकर्ताओं, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं विधि विद्यार्थियों के लिए एक अमूल्य संदर्भ सामग्री सिद्ध होगी। यह विमोचन न केवल प्रकाशन को सशक्त बनाने का प्रयास है, अपितु न्यायिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही न्याय तक पहुच को सरल, सुलभ और बहुभाषीय बनाने की दिशा में एक प्रसंशनीय कदम है। हम इस प्रयास में सहभागी विद्वानों, संपादकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों का हार्दिक आभार व्यक्त करते है।

संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली

(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति

श्री अजित कुमार

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति

श्री समीर जैन

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विक्रम डी. चौहान

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विवेक कुमार सिंह

सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

SAMIR SHARMA

Senior Advocate,

High Court, Allahabad.

प्रबुद्ध पाठकगण,

वर्ष 1944 में घटित "कानपुर बम विस्फोट प्रकरण" एक दमनकारी दौर का परिचायक है जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक चर्चित और विवादास्पद घटना के रूप में याद किया जाता है। वह एक ऐसा समय था जब देश भर में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों का क्रोध और विद्रोही भावना उच्चतम स्तर पर थी। कानपुर जो उद्योग एवं राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का एक गढ़ बन चुका था।

इस बम विस्फोट प्रकरण में अंग्रेजी सरकार ने कुछ क्रांतिकारियों पर लक्षित रूप से आरोप लगाए कि उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर बमबाजी करके राजनीतिक दबाव बनाने की योजना बनाई थी। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की जो उनके लिए 'क्रांतिकारी षड्यन्त्र' का एक उदाहरण बन गई।

इस प्रकरण के पीछे के क्रांतिकारी, जो अपने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व

न्यौछावर करने को तैयार थे, उन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा 'आतंकवादी' या राजकतावादी' कहा गया। 1944 का कानपुर बम विस्फोट प्रकरण, उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाता है जो आज़ादी की वेदी पर दिए गए। यह प्रकरण उस तीव्र इच्छाशक्ति का प्रतीक है, जिसने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 1944 के कानपुर बम विस्फोट प्रकरण को केवल एक आपराधिक कृत्य के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक कठिन दौर के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। यह उन गुमनाम नायकों की गाथा है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

आशा करता हूँ कि राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित हिन्दी में प्रकाशित ऐतिहासिक निर्णयों की श्रृंखला का यह संस्करण, आप सभी विद्वान पाठकगण के ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन बनेगी।

वरिष्ठ संपादक

समीर शर्मा

समीर शर्मा

वरिष्ठ अधिवक्ता

सारांश: कानपुर बम विस्फोट प्रकरण (1944-45)

यह 1944 के **'कानपुर बम विस्फोट प्रकरण' (Cawnpore Bomb Conspiracy Case)** का एक औपचारिक और विस्तृत विधिक सारांश प्रस्तुत है। यह सारांश उच्च न्यायालय के निर्णय, साक्ष्यों की प्रकृति और ऐतिहासिक संदर्भों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है।

- **न्यायालय:** माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- **पीठ:** माननीय मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद एवं माननीय न्यायमूर्ति ऑलसॉप
- **वाद संख्या:** आपराधिक अपील सं. 1028 वर्ष 1944 एवं अन्य संबद्ध मामले

1. परिचय एवं मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के तत्काल बाद की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। कानपुर, जो उस समय एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का एक मुख्य गढ़ बन गया था। इस मामले में कुल 13 मुख्य अभियुक्तों पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, अवैध हथियारों के निर्माण, और सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

अभियोजन पक्ष का मुख्य तर्क यह था कि अभियुक्तों ने एक संगठित समूह बनाया था जिसका उद्देश्य सरकारी मशीनरी को पंगु बनाना और युद्ध प्रयासों (द्वितीय विश्व युद्ध) में बाधा डालना था।

2. प्रमुख घटनाएँ और अपराध का स्वरूप

षड्यंत्र के क्रियान्वयन के दौरान दो बड़ी घटनाएँ दर्ज की गईं, जिन्होंने इस मामले की गंभीरता को निर्धारित किया:

- **कानपुर रेलवे स्टेशन विस्फोट (9 फरवरी 1943):** अभियुक्तों ने हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस को निशाना बनाते हुए रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के पास एक शक्तिशाली विस्फोटक लगाया था। इस विस्फोट में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और रेलवे की संपत्ति को व्यापक क्षति पहुँची। न्यायालय ने इसे 'मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा' माना।
- **निशात टॉकीज विस्फोट (11 फरवरी 1943):** एक सिनेमा हॉल में कम तीव्रता का पाइप बम विस्फोट किया गया। यद्यपि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसका उद्देश्य जनता और प्रशासन के मन में आतंक पैदा करना था।

3. षड्यंत्र का बुनियादी ढांचा (Secret Infrastructure)

इस समूह की विशेषता यह थी कि इन्होंने अत्यधिक पेशेवर तरीके से अपने संचालन केंद्रों का विस्तार किया था:

1. **नेशनल मोल्डिंग वर्क्स (ढलाईघर):** यह आनंद प्रकाश की फैक्ट्री थी। अभियोजन ने सिद्ध किया कि यहाँ रात के समय रिवॉल्वर के पुर्जे और बम के खोल (Shells) ढाले जाते थे।
2. **कुली बाज़ार और सीसमऊ केंद्र:** इन स्थानों का उपयोग रासायनिक प्रयोगों और विस्फोटक सामग्री (जैसे पोटेशियम क्लोरेट और गंधक) के भंडारण के लिए किया जाता था।
3. **पिक्रिक हाउस:** डॉ. शोम और राम गुलाम से संबंधित यह परिसर पिक्रिक एसिड जैसे घातक रसायनों के निर्माण का गुप्त प्रयोगशाला था।

4. साक्ष्य एवं विधिक बिंदु (Evidence and Legal Issues)

न्यायालय के समक्ष मुख्य चुनौती सह-अपराधी (Accomplice) की गवाही

और बरामदगी के बीच संतुलन बनाना था।

- **सह-अपराधी की गवाही (धारा 133, भारतीय साक्ष्य अधिनियम):** इस मामले में 'उमा शंकर' मुख्य सरकारी गवाह (Approver) बना। न्यायमूर्ति ऑलसॉप ने स्पष्ट किया कि यद्यपि एक सह-अपराधी की गवाही पर दोषसिद्धि कानूनी रूप से संभव है, लेकिन विवेक का तकाजा है कि इसकी पुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से हो। इस मामले में, उमा शंकर द्वारा बताए गए स्थानों से पुलिस ने ठीक वही सांचे और रसायन बरामद किए, जिनका उसने उल्लेख किया था।
- **इकबालिया बयान (Confessions):** अभियुक्तों बाबूराम और राम गुलाम के विस्तृत बयानों को न्यायालय ने 'स्वैच्छिक' माना। न्यायालय का तर्क था कि इन बयानों में दी गई तकनीकी जानकारी इतनी सटीक थी कि इसे पुलिस द्वारा गढ़ा जाना असंभव था।
- **अवैध सामग्री की बरामदगी:** पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अर्ध-निर्मित रिवॉल्वर, बम के खोल, और रसायनों की बरामदगी ने षड्यंत्र की पुष्टि में 'अंतिम कील' का काम किया।

5. अभियुक्तों की भूमिका और श्रेणीबद्ध विवरण

न्यायालय ने अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता के आधार पर वर्गीकृत किया:

- **मास्टरमाइंड:** आनंद प्रकाश (फैक्ट्री मालिक), हरभगवान (संपादक) और जी.डी. चावला को मुख्य योजनाकार माना गया।
- **तकनीकी विनिर्माणिकर्ता:** बजरंग सिंह और बाबूराम लोहे के काम और बम निर्माण के विशेषज्ञ थे।
- **सहायक:** जगदीश प्रसाद और राम गुलाम रसद और धन की व्यवस्था देखते थे।

न्यायालय ने आनंद प्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(ए) और 6, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 19 सपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 के तहत अपराध का दोषी पाया तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत सात साल के कठोर कारावास और भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 19 सपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी और ये सजाये साथ साथ चलाने का आदेश दिया गया । न्यायालय ने राम निरंजन की दोषसिद्धि और अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा की पुष्टि की तथा राम गुलाम और शोम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत अपराधों से बरी कर दिया , लेकिन अन्य धाराओं के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की। न्यायालय ने राम गुलाम को सुनाई गई कारावास की सजा को प्रत्येक धारा के तहत तीन वर्ष की अवधि तक कम कर दिया। ये सजाएँ एक साथ चलाने का आदेश दिया गया । शोम को सुनाई गई सजा को प्रत्येक धारा के तहत पहले से काटी गई कारावास की अवधि तक कम कर कर दिया गया और निर्देशित किया गया कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक न हो।

न्यायालय ने निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश द्वारा जगदीश प्रसाद को सुनाई गई सज़ा को बरकरार रखा और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी पाते हुए उसी धारा के तहत आजीवन निर्वासन की सज़ा सुनाई। ये सज़ाएँ साथ- साथ चलाने का आदेश दिया गया। शंभू दयाल, दलपत सिंह और परमेश्वरी को भारतीय दंड संहिता की धारा

120बी, 435/109 और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी पाया गया और उन्हें प्रत्येक धारा के तहत सात-सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। न्यायालय ने उन्हें भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 के तहत अपराध का भी दोषी पाया और उन्हें उस नियम के तहत तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, और शंभू दयाल को भारत रक्षा नियमावली के नियम 39 के तहत अपराध का भी दोषी पाया गया और उन्हें उस नियम के तहत तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत दंडनीय अपराध से मुक्त कर दिया।

न्यायालय ने बजरंग सिंह और बाबूराम की दोषसिद्धि और उन्हें निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सज़ा की पुष्टि की, सिवाय इसके कि धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत मृत्युदंड को आजीवन निर्वासन की सज़ा में बदल दिया गया। इसके अलावा, दोनों अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराधों का दोषी पाया गया और उनमें से प्रत्येक को उस धारा के तहत तीन वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गयी। ये सज़ाएँ साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया।

न्यायालय ने हरभगवान और जी.डी. चावला को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और विस्फोट अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और प्रत्येक धारा के तहत उन्हें सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्हें भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 के तहत अपराधों का भी दोषी पाया गया और उन नियमों के तहत उनमे से प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। ये सज़ाएँ साथ-साथ चलाने का आदेश पारित किया गया ।। खानोल्कर को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया गया और उस मामले में उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया, जब तक कि किसी अन्य मामले में उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक न हो। आनंद प्रकाश, हरभगवान, चावला, शंभू दयाल, दलपत और परमेश्वरी को अपनी-अपनी सज़ाएँ पूरी करने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया।

अस्वीकरण

ई- पुस्तिका मे प्रकाशित निर्णय को ए.आई. तकनीक का प्रयोग कर अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित निर्णय की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/ सुवास प्रकोष्ठ उत्तरदायी नहीं होगा ।

मूल निर्णय स्त्रोत :

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल पत्रावली
(विधि संग्रहालय, प्रयागराज में संरक्षित)

आपराधिक अपील सं. 1028 सन् 1944

संदर्भ सं. 1 सन् 1945
संबद्ध
शासकीय अपील सं. 72 सन् 1945
आपराधिक संदर्भ सं. 25 सन् 1945

एवं आपराधिक पुनरीक्षण सं. 132 सन् 1945

माननीय न्यायमूर्ति इकबाल अहमद, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय न्यायमूर्ति ऐलसोप (Allsop)
(माननीय न्यायमूर्ति ऐलसोप (Allsop) के अनुसार)

तेरह लोगों, जिनके नाम आनंद प्रकाश, हर भगवान, जी.डी. चावला, जगदीश प्रसाद, शंभू दयाल, बजरंग सिंह, दलपत सिंह, राम निरंजन, बाबूराम, परमेश्वरी उर्फ परभाकर, राम गुलाम, डी.बी. शोम और जी.एल. खानोल्कर हैं, पर कानपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विभिन्न आरोपों में मुकदमा चलाया गया। उन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत षड्यंत्र रचने और भारत रक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली के नियम 38 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इसके अलावा, उन सभी पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए और उनमें से कुछ पर हत्या, आगजनी या उस अपराध के लिए उकसाने, शस्त्र अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराध और भारत रक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली के नियम 39 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए। नियम 38 और 39 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत आरोपों का विचारण विद्वान न्यायाधीश द्वारा जूरी की सहायता से और अन्य आरोपों का विचारण मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता से किया गया। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि जगदीश प्रसाद, बजरंग सिंह, राम निरंजन सिंह, बाबूराम, राम गुलाम और डी. बी. शोम विभिन्न अपराधों के दोषी थे, लेकिन जगदीश प्रसाद, राम गुलाम और शोम को हत्या या हत्या के लिए उकसाने के उन अपराधों से बरी कर दिया गया, जिनका उन पर आरोप लगाया गया था। उन्होंने बजरंग सिंह और बाबूराम को मृत्युदंड, राम निरंजन सिंह को आजीवन निर्वासन, जगदीश प्रसाद और राम गुलाम को चौदह वर्ष के निर्वासन और डी.बी. शोम को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया था, उन्होंने अपील की है।

विद्वान न्यायाधीश ने मृत्युदंड की सज़ाओं को पुष्टि के लिए हमारे पास भेज दिया है। सरकार ने बरी किए जाने के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की है और जिन लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया गया है, उनकी सज़ाओं को बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर की है। जूरी ने पाया कि सभी अभियुक्त भारत रक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली के नियम 38 के तहत अपराधों के लिए दोषी थे और उनमें से एक, शंभू दयाल, नियम 39 के तहत अपराध के दोषी थे। उन्होंने यह भी पाया कि जगदीश प्रसाद, बाबूराम और बजरंग सिंह शस्त्र अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराधों के लिए दोषी थे और आनंद प्रकाश शस्त्र अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराध के लिए उकसाने के दोषी थे। विद्वान न्यायाधीश ने उनसे भिन्न राय व्यक्त की और मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के प्रावधानों के तहत हमारे पास भेज दिया है।

पहली नज़र में मामला कुछ पेचीदा लगता है, लेकिन असल में अभियुक्तों पर क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए बम और हथियार बनाने की साज़िश में शामिल होने और इसी साज़िश के तहत कानपुर रेलवे स्टेशन और एक सिनेमाघर में विस्फोट करने का आरोप लगाया गया था। जगदीश प्रसाद के पास एक रिवॉल्वर और शंभू दयाल तथा खानोल्कर के पास राजद्रोही साहित्य पाए जाने का आरोप था।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानपुर रेलवे स्टेशन

पर एक भयंकर विस्फोट हुआ था जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और स्टेशन परिसर को भारी नुकसान हुआ था। न ही इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कुछ दिनों बाद निशात टॉकीज़ नामक सिनेमाघर में विस्फोट हुआ था, जिसमें सौभाग्य से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और संपत्ति को भी बहुत कम नुकसान हुआ, क्योंकि यह एक छोटा विस्फोट था जो हॉल खाली होने पर हुआ था।

मुख्य साक्ष्य में एक सरकारी गवाह, उमा शंकर का बयान, चार अपीलकर्ताओं, बाबूराम, राम निरंजन, राम गुलाम और डी.बी. शोम के इकबालिया बयान और कथित तौर पर भारी मात्रा में आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी शामिल है। पुष्टिकरण के लिए सहायक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं।

चूँकि निचली अदालत ने इस सहायक साक्ष्य पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया, इसलिए यह तर्क दिया गया है कि कई अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सरकारी गवाह का साक्ष्य और स्वीकारोक्ति का साक्ष्य ही मौजूद है और ऐसे साक्ष्य, क़ानूनन, इन अभियुक्तों की दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहरा सकते। मैं समय आने पर साक्ष्यों पर चर्चा करूँगा और यह पता लगाऊँगा कि सरकारी गवाह और स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्तों के बयानों की पुष्टि किस हद तक हुई है, लेकिन मैं यहाँ इससे जुड़े क़ानूनी पहलू के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं हो सकता कि किसी सरकारी गवाह का अपुष्ट साक्ष्य किसी भी स्थिति में दोषसिद्धि को उचित न ठहराए, क्योंकि कोई भी न्यायालय किसी क़ानून के किसी निश्चित प्रावधान की अनदेखी नहीं कर सकता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 कहती है, "किसी अभियुक्त के विरुद्ध एक सह-अपराधी सक्षम गवाह होगा; और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि वह सह-अपराधी की अपुष्ट गवाही पर आधारित है।" दूसरी ओर, प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय आचरण के सामान्य क्रम को देखते हुए, यह भी उतना ही स्पष्ट है कि विशेष परिस्थितियों के अभाव में किसी सह-अपराधी का साक्ष्य तब तक विश्वसनीय नहीं होता जब तक कि उसकी पुष्टि सारवान विवरणों से न हो जाए। मात्र यह तथ्य कि ऐसा व्यक्ति अपराध में सहयोगी था, आम तौर पर यह सुझाव देगा कि उसके पास कोई उच्च नैतिक मानक नहीं थे, और आमतौर पर यह संदेह होगा कि वह दूसरों को, जो निर्दोष थे, फंसाकर खुद को या अपने वास्तविक सहयोगियों को बचाने का प्रयास कर रहा होगा। संपुष्टि की सामान्य आवश्यकता पर न्यायालय द्वारा कई मामलों में बल दिया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (बी) में विधानमंडल द्वारा भी इसे मान्यता दी गई है, लेकिन यह केवल एक सामान्य नियम है और कभी-कभी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जो बाह्य/संपुष्टि को अनावश्यक बना देती हैं। मुझे लगता है कि शायद कभी-कभी यह अनदेखा कर दिया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों की संभावना उस दृष्टांत में इंगित की गई है जिसका मैंने उल्लेख किया है। पूरा दृष्टांत इस प्रकार है-

"न्यायालय यह मान सकता है कि कोई सह-अपराधी तब तक विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके सारवान विवरणों की पुष्टि न हो जाएँ। लेकिन न्यायालयों को यह विचार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसा सिद्धांत उसके समक्ष उपस्थित विशेष मामले पर लागू होता है या नहीं-

(i). 'क', जो उच्च चरित्र का व्यक्ति है, पर किसी मशीनरी की व्यवस्था करते समय लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का मुकदमा चलाया जाता है; 'ख', जो समान रूप से अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, जिसने भी व्यवस्था में भाग लिया था, वह ठीक-ठीक वर्णन करता है कि क्या किया गया था, और 'क' तथा स्वयं की सामान्य लापरवाही को स्वीकार करता है और स्पष्ट करता है;

(ii). कई व्यक्तियों द्वारा एक अपराध किया जाता है, जिनमें से तीन अपराधियों क, ख और ग को मौके पर ही पकड़ लिया जाता है और एक-दूसरे से अलग रखा जाता है; प्रत्येक व्यक्ति घ को आरोपित करने वाले अपराध का विवरण देता है, और विवरण एक-दूसरे की इस प्रकार पुष्टि करते हैं कि पूर्व सहमति अत्यधिक असंभाव्य हो जाती है।"

शायद, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय किसी अन्य साक्षी पर तब तक विश्वास करेगा जब तक उसके पास यह सोचने का सकारात्मक कारण न हो कि उसका साक्ष्य झूठा है, जबकि वह किसी सरकारी गवाह पर तब तक विश्वास

नहीं करेगा जब तक उसके पास यह सोचने का सकारात्मक कारण न हो कि उसका साक्ष्य सत्य है। इसलिए मेरा निष्कर्ष यह है कि जूरी या तथ्य-निर्धारक न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में सरकारी गवाह के साक्ष्य की जाँच सभी परिस्थितियों के आलोक में करनी चाहिए और ऐसे साक्ष्य पर अविश्वास करने के सामान्य कारणों को निरंतर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन यदि ऐसे कारणों के बावजूद, वे या वह साक्ष्य पर विश्वास करते हैं क्योंकि यह किसी विशिष्ट अभियुक्त व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो वे उस व्यक्ति को केवल सरकारी गवाह के साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहरा सकते हैं और वास्तव में, ऐसा करना भी चाहिए।

स्वीकारोक्ति ऐसी प्रकृति की होती है जिसे लगभग उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए जैसे किसी सरकारी गवाह के साक्ष्य को देखा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अंतर्गत, जब एक से अधिक व्यक्तियों पर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा हो, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा स्वयं को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली स्वीकारोक्ति सिद्ध हो जाती है, तो न्यायालय ऐसी स्वीकारोक्ति के आधार पर ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ-साथ उस व्यक्ति के विरुद्ध भी विचार कर सकता है जिसने ऐसी स्वीकारोक्ति की है। इस तथ्य के अलावा कि स्वीकारोक्ति में दिया गया कथन सरकारी गवाह का कथन है, इसे अत्यंत सावधानी से लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें जिरह या स्पष्टीकरण का कोई अवसर नहीं होता है। यह भी अनिवार्य रूप से सत्य है कि वापस ली गई स्वीकारोक्ति अपना कुछ महत्व खो देती है क्योंकि उसमें बताए गए तथ्यों को उस व्यक्ति द्वारा नकार दिया जाता है जिसने स्वयं बयान दिया था; लेकिन यदि यह दिखाया जा सके कि वापस लिया गया बयान झूठा है, जिसमें स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति को अन्य साक्ष्यों से अपराध का दोषी साबित किया जाता है, तो वापस लिए गए बयान का मूल्य बहुत कम हो जाता है और यह सोचने का कारण कम हो जाता है कि मूल स्वीकारोक्ति झूठी थी। यहाँ फिर से न्यायालय को सभी परिस्थितियों के प्रकाश में स्वीकारोक्ति की जाँच करनी चाहिए, और मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा उद्धृत दृष्टांत से ऐसा प्रतीत होता है कि एक स्वीकारोक्ति, कुछ परिस्थितियों में, दूसरी स्वीकारोक्ति की पुष्टि कर सकती है। दृष्टांत के अलावा, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तथ्य के किसी प्रश्न पर निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति समान तथ्यों को बताने वाले एक बयान की तुलना में दो स्वतंत्र बयानों पर अधिक भरोसा करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 'सिद्ध' शब्द की परिभाषा के मद्देनजर यह हमेशा याद रखना चाहिए कि तथ्यों की जांच करते समय न्यायाधीश और जूरी किसी अन्य विवेकशील व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न स्थिति में नहीं होते हैं।

हमारे समक्ष प्रस्तुत विधि के प्रश्नों का निस्तारण करने के पश्चात्, मैं साक्ष्यों पर उनके मेरिट के आधार पर विचार करने के लिए आगे बढ़ता हूँ।

अभियोजन पक्ष का तर्क यह है कि कई लोग, जिनमें ज़्यादातर युवा थे, कानपुर के गांधी पार्क में या उसके आस-पास इकट्ठा होते थे और मिलते -जुलते थे। अगस्त 1942 के दंगों के समय, जब वे इस नतीजे पर पहुँचे कि युद्ध की प्रक्रिया में बाधा डालकर और भय व अशांति फैलाकर वे किसी न किसी तरह अपने देश को लाभ पहुँचाएँगे, तो उन्होंने तय किया कि वे इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हथियार और बम बनाएंगे। इस षडयंत्र की उत्पत्ति शोम और राम गुलाम के इकबालिया बयानों में वर्णित है। शोम एक बंगाली थे जो कानपुर के आनंद बाग में रहते थे और होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में काम करते थे। राम गुलाम शोम के साथ उसी इमारत में रहते थे और उनकी एक दुकान और लकड़ी का गोदाम था। दोनों व्यक्ति दोस्त बन गए और शतरंज खेलने के लिए गांधी पार्क जाया करते थे, और शोम के अनुसार, पार्क में या उसके पास स्थित एक श्रम कल्याण केंद्र में वॉलीबॉल खेलने के लिए भी जाया करते थे। पार्क में उनकी मुलाकात आरोपी आनंद प्रकाश, हरभगवान, जगदीश और चावला से होती थी। राम गुलाम ने कहा है कि ये लोग शोम से उनकी डिस्पेंसरी में मिलने आते थे और वह वहां उनसे मिलते थे। उन दोनों ने कहा कि इन लोगों और उन्होंने भी अगस्त अशांति के समय अपने देश के भविष्य पर चर्चा की और उन निष्कर्षों पर पहुंचे जिनका मैंने उल्लेख किया है। वे सभी इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें विध्वंसक गतिविधियाँ करनी चाहिए। शोम ने कहा है कि वे शुरू में रात में गश्त करते थे, जिससे मुझे लगता है कि उनका मतलब है कि वे मौका पड़ने पर शरारत करने के उद्देश्य से घूमते रहते थे, लेकिन उनका कहना है कि वे खुद अक्सर इन गश्तों में शामिल नहीं होते थे। राम गुलाम ने कहा है कि वह केवल बम बनाने के लिए सामग्री जुटाने के लिए सहमत हुए थे। दोनों के अनुसार, बाबूराम और बजरंग कुछ समय बाद इस षड्यंत्र में शामिल हुए। इन दोनों व्यक्तियों और अन्य स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्तों और सरकारी गवाह के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि षड्यंत्रकारियों ने विस्फोटक और बम के केस बनाने के लिए और रिवॉल्वर व कारतूस बनाने के लिए भी, कई घरों को किराए पर लिया था।

बाबूराम की कानपुर में एक पेंट की दुकान थी। उन्होंने कहा है कि उन्हें बजरंग से पन्ना लाल सोनार नाम के एक व्यक्ति ने मिलवाया था, जो अब फरार है, और बजरंग ने ही उन्हें इस षड्यंत्र में शामिल किया था। राम निरंजन बनारस में दलपत के स्कूल के साथी थे। वह कानपुर आ गए और हार्नेस एंड सैडलरी फ़ैक्टरी में क्लर्क बन गए। कानपुर में उनकी मुलाकात दलपत से हुई और उन्होंने उन्हें एक समाजवादी समूह के सदस्यों से मिलवाया, जिससे अभियुक्त आनंद प्रकाश जुड़े थे। इस समूह में भी विध्वंसकारी प्रवृत्तियाँ थीं। राम दुलारे त्रिवेदी नाम का एक व्यक्ति, जिसे काकोरी डकैती कांड में दोषी ठहराया गया था, उन्हें डकैती और इसी तरह के अन्य अपराध करने के लिए उकसाया करता था। वह और दलपत, दोनों कानपुर में छात्र संघ के सदस्य थे और दलपत, वास्तव में, उनके मुखिया थे। इस तरह राम निरंजन को इस षड्यंत्र में शामिल किया गया और वह आनंद प्रकाश, हरभजन, चावला, जगदीश और बाबूराम के साथ इसमें शामिल हो गए। आनंद प्रकाश विज्ञान स्नातक हैं और कानपुर में सनेजा आयरन फ़ैक्टरी के मालिक थे। हरभगवान एक हिंदी अखबार के उप-संपादकों में से एक थे। चावला, जिनका पूरा नाम घनश्याम दास चावला है, केंद्रीय आयुध डिपो में क्लर्क थे और जगदीश शहर के एक धनी कपड़ा व्यापारी के बेटे थे। बजरंग, बाबूराम की तरह, लोहे के यांत्रिक कारीगर थे। राम निरंजन ने बताया है कि परमेश्वरी अक्सर उनके घर आते थे और ऐसा लगता है कि वह भी इस षडयंत्र में शामिल थे। सरकारी गवाह उमाशंकर, एक लोहार था जो फैजाबाद से कानपुर अपने पिता के पास आया था, जो रमाशंकर कंपनी में काम करते थे और जहाँ बजरंग भी काम करते थे। इस तरह उनकी मुलाकात बजरंग से हुई और उनसे दोस्ती हो गई। बजरंग ने धीरे-धीरे उन्हें षडयंत्र में शामिल कर लिया।

सरकारी गवाह के बयानों और स्वीकारोक्ति से पता चलता है कि षडयंत्र के सदस्यों ने सबसे पहले कुली बाज़ार में एक घर लिया था जहाँ वे रसायन जमा करते थे और विस्फोटक बनाने के प्रयोग करते थे। इस घर का इस्तेमाल कुछ षडयंत्रकारियों के निवास के रूप में भी किया जाता था। छात्र संघ से जुड़ी गतिविधियों के कारण दलपत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वह फरार थे और एक समय उन्होंने इसी घर में शरण ली थी। मामले में पिक्रिक हाउस के रूप में वर्णित अन्य परिसर, उस इमारत में किराए पर लिया गया था जिसमें शोम और राम गुलाम रहते थे। इन इमारतों का मालिक लखनऊ में था और शोम को उसने इमारत में परिसर किराए पर देने और किराया वसूलने का काम सौंपा था। इसलिए, उन्होंने ही इन परिसरों को षड्यंत्रकारियों को किराए पर दिया था। बाद में, जनवरी के मध्य में, आनंद प्रकाश ने हथियार और बम के केस बनाने के उद्देश्य से कुछ कमरे लिए और उनमें उमा शंकर को स्थापित किया। बजरंग ने इन कमरों में काम के लिए उमा शंकर की मदद की। इस जगह का वर्णन ढलाईघर के रूप में किया गया है। यह स्पष्ट रूप से एक साधारण कार्यशाला थी और इसे नेशनल मोल्डिंग वर्क्स कहा जाता था। यह दिन के समय सामान्य तरीके से ऑर्डर पर काम करता था, लेकिन रात में इसका इस्तेमाल रिवॉल्वर और बम के केस बनाने के प्रयोगों के लिए किया जाता था। अन्य परिसर सीसमऊ में किराए पर लिए गए थे, और इसे सीसमऊ स्टोर हाउस कहा जाता था और एक को चकला कहा जाता था। मोंढा टोली नामक एक अन्य क्वार्टर बाद में सामग्री के भंडारण के उद्देश्य से गिरजा शंकर नामक एक व्यक्ति द्वारा किराए पर लिया गया था। ये इमारतें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बाद में पुलिस ने इनमें से कुछ या सभी का निरीक्षण किया था और इनमें से आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी। सरकारी गवाह के बयानों और स्वीकारोक्ति से सामान्य तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि अगस्त या सितंबर 1942 से लेकर जनवरी के अंत या फरवरी 1943 की शुरुआत तक प्रयोग और तैयारी का एक दौर चला था। इस अवधि के शुरुआती दौर में हथियार, रसायन और बम बनाने की सामग्री मुस्लिम इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में ब्रह्मा नंद या मुनीम जी नामक एक व्यक्ति के घर में रखी जाती थी। इस व्यक्ति ने इस मामले में गवाही दी है। जब कुली बाजार स्थित घर लिया गया तो इन सामग्रियों को उसमें ले जाया गया और बाद में कुछ या सभी सामग्रियों को उस दूसरे परिसर में ले जाया गया जिसका मैंने उल्लेख किया है।

साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रकार की गतिविधियां नवाबगंज में एक अन्य समूह द्वारा संचालित की जा रही थीं, जिसके संपर्क में कुछ षड्यंत्रकारी थे; लेकिन हम केवल वर्तमान षड्यंत्र के अस्तित्व में आने के बाद उससे जुड़ी घटनाओं से पर विचार कर रहे हैं और मैंने प्रारंभिक गतिविधियों का उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उस सामान से कुछ संबंध था जो उस समय ब्रह्मानंद के पास संग्रहीत था जब उमाशंकर अन्य षड्यंत्रकारियों के संपर्क में आए थे।

इस समय विभिन्न बयानों के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है।

उनसे सामान्य तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि षड्यंत्रकारियों ने एक आंतरिक परिषद जैसा संघ बनाया था जो आम तौर पर उनकी गतिविधियों और सहायकों को नियंत्रित करता था जो विभिन्न तरीकों से सहायता करते थे और समय-समय पर विचार-विमर्श में भाग लेते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आनंद प्रकाश, हरभगवान और जगदीश नेताओं की स्थिति में थे। उमा शंकर मुख्य रूप से बम के केस के निर्माण से संबंधित थे और साजिश के नेता बाबूराम और बजरंग के साथ बमों के निर्माण के लिए आवश्यक रसायन और तंत्र के बारे में देखते थे, हालांकि बजरंग ने लोहे के काम में उमा शंकर की भी सहायता की थी। राम गुलाम रसायनों की खरीद देखते थे। शोम ने अपने भवन में कमरे खरीदने में मदद की और अन्य लोग चर्चाओं में शामिल होते थे और जब आवश्यक हो तो अपनी सलाह देते थे।

षड्यंत्रकारियों ने स्वतंत्रता दिवस, यानी 26 जनवरी, 1943 को कोई निश्चित कार्रवाई करने का निर्णय लिया था, लेकिन आनंद प्रकाश, हरभगवान और चावला को भारत रक्षा नियमावली के नियम 129 के प्रावधानों के तहत 13 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्रवाई स्थगित कर दी जाए क्योंकि इस बात का खतरा था कि गिरफ्तार किए गए लोग पुलिस को सूचना दे सकते हैं। हालाँकि, ऐसा कहा जाता है कि वे जेल से दूसरों को कुछ निश्चित कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले पत्र बाहर भेजने में कामयाब रहे, और फिर दो बम लगाने का निर्णय लिया गया, एक 9 फरवरी को रात 9.30 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पर और दूसरा लगभग आधी रात को कोतवाली में। उस समय तक दो बड़े बम और एक पाइपिंग के टुकड़ों से बने तीन छोटे बम तैयार हो चुके थे। उनके केस आंशिक रूप से ढलाईघर में बनाए गए थे, लेकिन कुछ काम कानपुर की अन्य फर्मों द्वारा किया जाना था और इस काम से जुड़े कई लोगों के साक्ष्य पुष्टिकरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। विस्फोटक पिक्रिक हाउस में बनाए गए थे, और कुछ चीजें उस समय तक सीसमऊ में संग्रहीत की गई थीं। सामग्री, यानी विस्फोटक और केस कुली बाजार हाउस ले जाए गए, जहाँ अंततः बम तैयार किए गए। यह व्यवस्था की गई थी कि जगदीश और राम निरंजन एक बड़े बम को रेलवे स्टेशन ले जाएंगे, और उसके बाद राम निरंजन अन्य बमों को कोतवाली ले जाएंगे। जब बम तैयार हो गए तो जगदीश कुली बरार हाउस से एक बड़े बम को सरजू प्रसाद नामक व्यक्ति के घर ले गए और उसे वहीं छोड़ दिया। वह दूसरे बम को ढलाईघर ले गया। राम निरंजन शाम लगभग 7.30 बजे ढलाईघर आए और उन्हें जगदीश द्वारा सरजू प्रसाद के घर ले जाया गया, जहां से उन्होंने बम लिए और उसे रेलवे स्टेशन ले गए। इस समय एक और आदमी, जिसका पता नहीं चल पाया है और जिसका किसी भी बयान में पहले से साजिश में शामिल होने के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, घटनास्थल पर पहुंचा। उसने स्टेशन के बाहर उस जगह से बम लिया जहां जगदीश और राम निरंजन ने इसे पहुंचाया था और एक कुली की मदद से इसे ओवरब्रिज के नीचे रख दिया। जब हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस स्टेशन पर थी तब यह फट गया और तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए और काफी भौतिक क्षति हुई। राम निरंजन दूसरा बम लाने के लिए ढलाईघर वापस गए लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय तक वह अपना धैर्य खो चुके थे, उस समय बाबू, बजरंग और उमा शंकर ढलाईघर में थे। राम निरंजन एक इक्के पर बम ले गए लेकिन कुछ ही क्षणों में वापस आ गए और कहा कि पैकिंग ढीली थी। मैं यह बता दूं कि ये दोनों बम लकड़ी के बक्सों में रखे गए थे एक साधारण घड़ी की सुइयों से बिजली के तार जोड़े गए थे ताकि किसी विशेष समय पर संपर्क होने पर बम विस्फोट किया जा सके। जब राम निरंजन बम वापस लाए तो बक्सा खोला गया और बम व घड़ी को फिर से पैक किया गया, लेकिन राम निरंजन ने कहा कि वह जगदीश के आने तक इंतज़ार करेंगे। चूँकि जगदीश नहीं आए और विस्फोट का समय नज़दीक आ रहा था, इसलिए तंत्र को बंद कर दिया गया और घड़ी को बाहर निकालकर ढालगीर में सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेशन पर विस्फोट के बाद षड्यंत्रकारी अपने किए से कुछ हद तक भयभीत थे। यह स्वाभाविक है कि एक काल्पनिक बम विस्फोट और वास्तव में ऐसे विस्फोट में काफ़ी अंतर होता है। जगदीश चिंतित थे कि षड्यंत्रकारियों की गतिविधियाँ समाप्त न हों और उन्होंने बाबूराम, बजरंग और उमाशंकर को 11 फ़रवरी को निशा टॉकीज़ में एक और बम लगाने के लिए राजी किया। हालाँकि, यह पाइपिंग के एक टुकड़े से बना एक बहुत छोटा बम था और इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि तीनों लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि हॉल खाली होने तक यह न फटे। वे सामान्य तरीके से सिनेमाघर में गए और एक सीट के नीचे बम बाँध दिया, लेकिन उसे फॉस्फोरस से विस्फोट करना था और उन्होंने उस पर तब तक फॉस्फोरस नहीं डाला जब तक कि शो खत्म नहीं हो गया और लोग वहाँ से चले नहीं गए। यह आखिरी बार था जब कोई ठोस कार्रवाई की गई।

इसके बाद, जो अभियुक्त पहले से जेल में नहीं थे, उन्हें समय-समय पर षड्यंत्र के सिलसिले में या अन्य आधारों पर गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा की गई जाँच के परिणामस्वरूप तथ्य प्रकाश में आए।

मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दलपत सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। उन्हें 13 अप्रैल, 1943 को इंस्पेक्टर हेत राम ने राम निरंजन के घर से गिरफ्तार किया था। इस गवाह ने गवाही दी है कि जगदीश उस समय राम निरंजन और दलपत के साथ थे, लेकिन गवाह के पास उन्हें गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था। राम निरंजन को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान से इनकार करने में दलपत का समर्थन करने का प्रयास किया था। उन्होंने स्वयं सुझाव दिया है कि जगदीश मौजूद थे क्योंकि उन्होंने अपने इकबालिया बयान के अंत में कहा है कि चौधरी हेत राम जगदीश को जानते थे लेकिन दलपत को गिरफ्तार करते समय उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इस षड्यंत्र मामले की जांच करने वाले उपनिरीक्षक गुप्ता के अनुसार, दलपत ने ढलाईघर के अस्तित्व की जानकारी दी थी और इसके परिणामस्वरूप उस स्थान पर नजर रखी गई थी, क्योंकि पुलिस ने बजरंग को गिरफ्तार करना महत्वपूर्ण समझा था, जिसके पास बम होने का संदेह था। 26 अप्रैल की रात को पुलिस ने प्रभाकर को ढलाईघर के दरवाजे पर खड़ा देखा, जो कि आधा खुला हुआ था। सब-इंस्पेक्टर को बुलाया गया और उसने प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया। उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद की कि वह आदमी बजरंग होगा, लेकिन उसने पाया कि वह नहीं था। सब-इंस्पेक्टर ने बजरंग का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आए। कमरों की औपचारिक तलाशी लेने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने कालीचरण नामक एक व्यक्ति से ताला मंगवाया और कमरों को बंद करने के बाद, कालीचरण को चाबी रखने के लिए दे दिया। प्रभाकर ने उस रात साजिश के बारे में जानकारी दी, लेकिन अगली रात तक तलाशी लेना असंभव था। अगली रात प्रभाकर एक पुलिस दल को सबसे पहले सीसमऊ स्टोर्स के नाम से जानी जाने वाली जगह पर ले गया। उस जगह की तलाशी ली गई और पुलिस को बोतलों के आकार के चार बमों के डिब्बे, सात सेर शोरा और कुछ अन्य रसायन, कुछ कच्चे लोहे की शाफ्ट झाड़ियाँ और पीले रंग से सने ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़े मिले। इस अंतिम वस्तु का महत्व यह है कि पिक्रिक एसिड एक पीला दाग बनाता है। सीसमऊ स्टोर से दल ढलाईघर गया, कालीचरण को बुलाया गया और चाबी लाई गई। पुलिस को पास और निहाई में लोहे के 180 छोटे टुकड़े मिले, वे ज्यादातर शाफ्ट झाड़ियों के टुकड़े थे। उन्होंने चार लोहे के डाट भी पाए जिनके बीच में छेद थे, तीन छोटे लोहे के डाट, एक लोहे की छड़ का टुकड़ा, दो गोलियां, बिजली के तार का एक टुकड़ा, पीले दाग वाला एक कागज़ का टुकड़ा, शाफ्ट झाड़ियों के आरेख वाला एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, बाबूराम द्वारा लिखा गया एक आवेदन भी पीले रंग का था, और कुछ किताबें और अन्य कागज़ात। तलाशी पूरी नहीं हुई क्योंकि पुलिस को अन्य स्थानों पर जाना था और पहले ही देर हो रही थी। कमरों को बंद कर दिया गया और चाबी फिर से कालीचरण को सौंप दी गई। इसके बाद प्रभाकर पुलिस को मोंढा टोली में सरजू के घर ले गया जहां प्रभाकर ने कहा था कि जगदीश और शंभू मिल सकते हैं। वे सरजू प्रसाद के बेटे तपेश्वरी के साथ ऊपरी मंजिल के घर में पाए गए। जगदीश के तकिये के नीचे एक रिवॉल्वर थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जगदीश के पास एक रूमाल थी जिसमें एक चाबी बंधी थी, और उन्होंने पुलिस को अन्य स्थानों पर ले जाने की पेशकश की। वह उन्हें सरजू के घर से लगभग चालीस या पचास कदम दूर मोंढा टोली में एक अन्य घर में ले गए। उन्होने इस जगह को अपने रूमाल से बंधी चाबी से खोला। इस घर में ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं मिला। वहां एक कैनवास का जूता था जो प्रभाकर के पैरों में फिट होता था। इसके बाद जगदीश पुलिस को मोहल्ला चकला स्थित उस घर में ले गया, जहां उन्हें एक अलमारी में एक जिंदा बम, चीनी मिट्टी का एक जार मिला जिसमें थोड़ा तेजाब था, एक मूसल और खरल, एक घड़ी, एक बोतल जिसमें कुछ तरल पदार्थ था, पीले रंग के पाउडर का एक पैकेट, तेजाब की गंध वाली कुछ गोलियां और एक टिन मिला जिसमें कुछ काला पेस्ट था। वहाँ से जगदीश पुलिस को कुली बाज़ार वाले घर ले गए। वहाँ उन्हें ढलाईघर में मिले लोहे के टुकड़ों जैसे कई टुकड़े, पीले दाग लगे टूटे हुए काँच के टुकड़े, सफ़ेद पाउडर का एक पैकेट और पीले दाग वाली सवा पाव रुई मिली। वहाँ से जगदीश पुलिस को पिक्रिक हाउस ले गए, जहाँ उन्हें गंधक की गंध वाली पीले रंग की फर्श की खुरचनी से भरी एक बाल्टी, पुराने और फटे चमड़े के दस्ताने, तेज़ाब की गंध वाली एक टूटी हुई बोतल, पीले दाग लगे ब्लॉटिंग पेपर के कुछ टुकड़े, थोड़ी रुई और पीले रंग से सनी एक रजाई, एक टोपी और पीले दाग लगे कुछ चिथड़े मिले। ये चीज़ें छत पर पड़े कूड़े के ढेर से बरामद की गईं, लेकिन उस समय ढेर की बहुत ध्यान से जाँच और तलाशी नहीं ली गई थी। सब-इंस्पेक्टर ने गवाही दी कि उसे घर के अंदर पीले रंग से रंगा एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन मिला था, लेकिन उसने उसे उस समय अपने कब्जे में नहीं लिया। जगदीश, शंभू और तपेश्वर को हिरासत में रखा गया। 29 अप्रैल को ढलाईघर की फिर से तलाशी ली गई और एक काँच का सिलेंडर और लोहे के दो गोल टुकड़े मिले। लेकिन बाद वाले पर रिवॉल्वर के चैंबर का निशान था। 13 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि फरार अभियुक्त पन्ना को मुस्लिम इंटरमीडिएट कॉलेज के पास

एक खाई में कुछ गोले या खोखे फेंकते देखा गया है। इसके बाद वे उस जगह गए और कई चीज़ें बरामद कीं, यानी लोहे की चादरों से बने दो पूरे बम के खोल और कुछ अन्य खोल, लोहे की पाइपिंग के टुकड़ों को बम में बदलने के लिए बंद करने वाले कुछ स्टॉपर, और एक रिवॉल्वर का चैंबर और अन्य हिस्से। पुलिस को यह भी पता चला कि उन्हें सरकारी गवाह के पिता, हर प्रसाद के घर में कुछ रसायन मिलेंगे, इसलिए उन्होंने उसकी तलाशी ली। उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड का एक जार, एसिड की गंध वाली दो बोतलें, लोहे की चादरों से बने दो बम के खोल, लोहे की मोटी चादर का एक टुकड़ा और लोहे के दो टुकड़े मिले, जो फ्यूज जलाने वाले उपकरण के पुर्जे लग रहे थे। 1 मई को, श्री एम.ए. वारसी, जो उस समय पुलिस इंस्पेक्टर थे, ने बजरंग को गिरफ्तार कर लिया। बजरंग ने एक ऐसा घर दिखाने की पेशकश की जहाँ उन्हें स्टेशन पर फटे बम जैसा एक ज़िंदा बम और कुछ अन्य सामान मिल सके। वह पुलिस अधिकारियों को सीसमऊ में बिशेश्वर के एक घर ले गए। उस घर के एक कमरे में पुलिस को सात सेर गंधक, लगभग दो पाउंड बारूद, डेढ़ सेर से ज़्यादा कॉपर सल्फेट, थोड़ा फॉस्फोरस, तीन पीली कांच की नलियाँ, थोड़ा सा पोटाश पाउडर, साल्टपीटर और एक अन्य रसायन, थोड़ा पिक्रिक एसिड, 200 पर्क्यूशन कैप, पिक्रिक एसिड से रंगी आठ कांच की नलियाँ, नारियल के आकार के चार ज़िंदा बम, दो शंकु के आकार के ज़िंदा बम और एक लकड़ी के बक्से में बंद एक बड़ा ज़िंदा बम मिला। बक्से में रुई और कालीन के टुकड़े भरे हुए थे। उन्हें एक प्लग, एक लकड़ी का बक्सा जिसमें रसायन और रासायनिक उपकरण, कुछ रुई, कुछ गोलियां और कारतूस, पिक्रिक एसिड से भरे चार कांच के जार और बारूद से भरी बोतलें भी मिलीं। इस मामले से जुड़ी सूचना मिलने पर खानोल्कर को 6 अप्रैल को कोल्हापुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाबूराम को 17 जुलाई, 1943 को ग्वालियर में पुलिस को दी गई सामान्य सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी की सूचना इंस्पेक्टर गुप्ता को दी गई, जिन्होंने जाकर उनसे पूछताछ की। ग्वालियर के सिटी मजिस्ट्रेट ने उनका इकबालिया बयान दर्ज किया। पुलिस ने राम गुलाम को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया और ये दोनों, अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार, इस मौके का फायदा उठाकर हरदोई जिले के एक गाँव में भाग गए, जो राम गुलाम का घर था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें चिट्ठियाँ मिलीं जिनमें कहा गया था कि उन्हें वापस लौट आना चाहिए क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा। वे वापस लौटे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राम गुलाम को 23 या 29 जुलाई को और शोम को 6 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। सरकारी गवाह उमा शंकर का पता दिल्ली में चला और उन्हें 4 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 8 सितंबर को कानपुर में अपना इकबालिया बयान दिया। राम गुलाम ने 31 जुलाई को और शोम ने 8 अगस्त को अपना इकबालिया बयान दिया।

गिरफ्तारियों और तलाशियों के बारे में पुलिस के सबूत हैं जो कुछ गवाहों के साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं, जिन पर मुझे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता। यह तर्क दिया गया है कि यह एक असाधारण बात थी कि राम गुलाम पिक्रिक हाउस की तलाशी के गवाहों में से एक थे, लेकिन अन्य गवाह भी थे और ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखाए कि सब-इंस्पेक्टर उस समय जानता था कि राम गुलाम इन अपराधों में सहयोगी या साजिश का सदस्य थे। भले ही उनके साक्ष्य को खारिज कर दिया जाए, अन्य गवाहों के साक्ष्य तथ्यों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इन दोषकारी सामानों की बरामदगी सरकारी गवाह के बयानों और स्वीकारोक्ति में कुछ तत्वों की मजबूत पुष्टि थी। विद्वान न्यायाधीश ने बजरंग के मामले पर विचार करते हुए इस बिंदु पर चर्चा की है जिसे उन्होंने दोषी ठहराया है। उन्होंने उस संबंध में अन्य पुष्टिकारी साक्ष्यों पर भी चर्चा की है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसे दोहराना अनावश्यक है। उस व्यक्ति ने निस्संदेह मोंढा टोली के उस कमरे की ओर इशारा किया, जिसे उसने गिरजा शंकर से किराए पर लिया था और जिसमें जीवित बम और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं। विस्फोटकों से संबंधित अधिकारियों के विशेषज्ञ साक्ष्य ने स्थापित किया है कि पूरी संभावना है कि ये बम स्टेशन पर फटे बम के समान ही थे और यह तथ्य स्वीकारोक्ति के एक हिस्से और सरकारी गवाह के बयान की दृढ़ता से पुष्टि करता है। गिरजा शंकर ने गवाही दी कि बजरंग ने वह कमरा किराए पर लिया था जहाँ बम मिला था। एक अन्य गवाह राम दत्त ने साबित किया कि चकला के उस घर पर उनका कब्जा था, जहाँ से निशात टॉकीज में फटे बम के समान एक बम बरामद किया गया था। तीन गवाहों ने गवाही दी कि बजरंग के पास जूही कारखाने में बने नुकीले आकार के बम के खोल थे। अभियुक्त ने इस कारखाने को ऑर्डर देने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि वह ऑर्डर वैक्यूम बॉक्स से संबंधित है। उन्होंने इस तथ्य को स्थापित करने या अपने खिलाफ गवाही देने वाले तीन गवाहों का खंडन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। कृष्ण पाल और जगन्नाथ ने साबित किया था कि बजरंग और बाबूराम ने इनमें से चार केसों में स्क्रू श्रेड किसी दूसरी फैक्ट्री में बनवाए थे। स्वीकारोक्ति के अनुसार, इनमें से तीन केसों को बम में बदल दिया गया था और दो बम अभियुक्तों के पास से मिले थे। कृष्ण पाल ने गवाही दी है कि वह धागा बनाने के लिए देय राशि लेने ढलाईघर गए थे। उन्होंने

वहाँ बाबूराम, बजरंग और उमा शंकर को अन्य लोगों के साथ देखा और उन्होंने उन्हें प्लग दिखाए जिनमें उन्होंने छेद कर रखे थे। उन्हें ये छेद खुद करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी ड्रिल खराब थी। यह साक्ष्य सीधे तौर पर उमा शंकर के बयान की पुष्टि करता है, जिन्होंने उल्लेख किया था कि पाल ब्रदर्स का मालिक ढलाईघर में अपना पैसा लेने आया था और उसे दिखाया गया था कि ढलाईघर के लोग उन छेदों को ड्रिल करने में कामयाब रहे थे जिन्हें वह ड्रिल करने में असफल रहा था। बाबूराम ने अपने इकबालिया बयान में यह भी कहा था कि वह और बजरंग पाल ब्रदर्स गए थे और उन्होंने धागे बनवाए थे। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विद्वान न्यायाधीश का बजरंग को दोषी मानना सही था। सामग्री की बरामदगी, बमों का विस्फोट, कम से कम बजरंग सिंह का अपराध सभी तथ्य हैं जो साजिश के अस्तित्व के बारे में सबूत की पुष्टि करते हैं और मेरे विचार से, कोई भी एक पल के लिए भी संदेह नहीं कर सकता कि साजिश मौजूद थी।

विद्वान न्यायाधीश ने बाबूराम के विरुद्ध साक्ष्यों पर भी चर्चा की है। यह तथ्य कि इस व्यक्ति को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्होंने ग्वालियर में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया था, अपने आप में यह मानने का एक ठोस आधार है कि वह ब्रिटिश भारत की पुलिस के प्रभाव में काम नहीं कर रहा था, जो इस षडयंत्र की जाँच कर रही थी। जब उस व्यक्ति को कानपुर लाया गया, तो उन्होंने मजिस्ट्रेट को शहर का भ्रमण कराया और उन्हें षडयंत्रकारियों से संबंधित विभिन्न स्थान दिखाए। बजरंग के खिलाफ कृष्णपाल और अन्य गवाहों के साक्ष्य इस व्यक्ति को भी दोषी ठहराते हैं। उन्होने स्वीकार किया कि वह पिक्रिक हाउस में रहते थे और विस्फोटक विभाग के सहायक निरीक्षक श्री मुखर्जी की गवाही से पता चला है कि इस जगह का इस्तेमाल निस्संदेह पिक्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि वह बजरंग के साथ कुली बाजार वाले घर में रहता था और इससे पता चलता है कि वे दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। कुली बाजार हाउस के भूतल पर रहने वाले बाल मुकुंद नामक एक बढ़ई ने भी गवाही दी है कि उसने 9 फरवरी को इस व्यक्ति को घर में सामान लाते देखा था और उसे दो बक्से निकालने में मदद करते भी देखा था, जिनमें से एक वह था जिसमें बड़ा ज़िंदा बम मिला था। कृष्ण बिहारी ने गवाही दी है कि यह व्यक्ति सीसमऊ स्टोर हाउस गया था जहाँ से शंक्वाकार बम के डिब्बे बरामद किए गए थे। विद्वान न्यायाधीश ने राम निरंजन द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर भी विश्वास किया है। इस इकबालिया बयान की हमारे सामने कड़ी आलोचना की गई है क्योंकि 14 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद से लेकर 1 जून तक, जब उन्हें जेल भेजा गया, राम निरंजन को पुलिस हिरासत में रखा गया था। इसके पीछे यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि पुलिस नहीं चाहती थी कि उसके साथी यह सोचें कि उसने इकबालिया बयान दिया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बात दूसरों को सावधान कर देगी। यह याद रखना चाहिए कि यह कोई साधारण मामला नहीं था जिसमें पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा दिलाने में लगी हो जिसे वह गिरफ्तार कर सकती हो। यह एक ऐसा मामला था जिसमें पुलिस एक खतरनाक साजिश की जाँच कर रही थी और उसके सरगनाओं को पकड़ने तथा साजिश का अंत करने में लगी थी। इसलिए, यह समझा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा कोई कदम न उठाना ज़रूरी समझा जिससे ये सरगना पकड़े जाने से बच सकें। यह तथ्य कि वह व्यक्ति लंबे समय से पुलिस हिरासत में था, उसके इकबालिया बयान पर कुछ संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन कुछ और भी परिस्थितियाँ हैं जो यह मानने पर मजबूर करती हैं कि यह सच है। यह व्यक्ति मजिस्ट्रेट को उन विभिन्न जगहों पर ले गया जिनका उसने अपने इकबालिया बयान में ज़िक्र किया था। उसने अन्य जगहों के अलावा, ढलाईघर और सरजू के घर की ओर इशारा किया जहाँ से उसने और जगदीश ने पुलिस स्टेशन जाने से पहले बम लिया था। इस बिंदु पर उसकी गवाही की पुष्टि सरजू ने की है। इस बात के भी सबूत हैं कि उसने हार्नेस और सैडलरी फ़ैक्टरी से उन महत्वपूर्ण समयों पर छुट्टी ली थी जैसा उसने बताया है। उसका तर्क है कि उसने छुट्टी इसलिए ली क्योंकि वह सचमुच बीमार था और उसने इस आशय के चिकित्सीय प्रमाण भी प्रस्तुत किए, लेकिन जाँच करने पर यह प्रमाण बेकार प्रतीत होता है। उस व्यक्ति ने बीमारी के आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन किया था और डॉक्टरों को बताया था कि उसे पेचिश और दस्त हो रहे हैं। डॉक्टर ने उसे प्रमाण पत्र तो दिए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन्होंने उसकी किसी भी तरह से जाँच की थी। उसके अपने बयान की पुष्टि के लिए उन्होंने निस्संदेह उसके लक्षणों के बारे में पूछताछ की और उसके कहे अनुसार उसे प्रमाण पत्र दिया। यह एक विचित्र तथ्य है कि वह 8 फ़रवरी तक छुट्टी पर था, 9 फ़रवरी को जब विस्फोट हुआ, उस दिन छुट्टी थी और वह 10 फ़रवरी को ड्यूटी पर लौटा। यह स्पष्ट है कि उसका यह कहना कि वह इतना बीमार था कि बम लगाने नहीं जा सकता था, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान न्यायाधीश का यह मानना सही था कि यह व्यक्ति षडयंत्र में शामिल था और जैसा कि उसने कहा, उसने बम को स्टेशन तक पहुँचाने में मदद की थी।

राम गुलाम ने अपनी गिरफ़्तारी के तीन दिन बाद, 31 जुलाई, 1943 को अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने अपने घर के सामने फुटपाथ पर एक जगह की ओर इशारा किया जहाँ उन्होंने बताया कि कुछ आपत्तिजनक चीज़ें दबी हुई हैं। गवाहों की मौजूदगी में उस जगह की खुदाई की गई और पुलिस को एक ज़िंदा शंक्वाकार बम, तेज़ाब से भरा एक जार और दो बम के केस मिले। जगन्नाथ नाम के एक गवाह की गवाही भी है कि राम गुलाम ने 30 नवंबर से 16 जनवरी के बीच उससे 17 सेर गंधक खरीदा था। अभियुक्त ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मेरे फैसले में, तलाशी के गवाहों की गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि बम और तेजाब का जार उसके घर के सामने गड़ा हुआ मिला था, और उनकी बरामदगी इस व्यक्ति के कबूलनामे की बहुत मजबूत पुष्टि है। मेरा मानना है कि विद्वान न्यायाधीश का यह मानना सही था कि राम गुलाम इस साजिश के सदस्य थे।

शोम ने अपनी गिरफ्तारी के दो दिन बाद अपना इकबालिया बयान दिया। इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने पिक्रिक हाउस बाबूराम को किराए पर दिया था और यह तथ्य कि बाबूराम उसमें रहते थे, लोख नारायण नामक एक गवाह की गवाही से साबित होता है, जिस पर मुझे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता। शोम ने कहा है कि उसने स्वदेशी मिल में काम करने वाले एक मैकेनिकल इंजीनियर राजा राम श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को घर किराए पर दिया था, लेकिन बचाव पक्ष ने यह साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया कि ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में था, और सरकारी गवाह के साक्ष्य और इकबालिया बयान से यह साबित होता है कि राजा राम का नाम बाबूराम ने लिया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शोम कमरा किराए पर देने में शामिल थे, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कमरे का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया गया था। परिस्थितियाँ अन्य सभी निश्चित सबूतों की पुष्टि करती हैं कि शोम इस साजिश के सदस्य थे और मैं न्यायाधीश के साथ इस बात पर विश्वास करता हूँ कि वह शामिल थे।

इस प्रकार, हम इस स्थिति में हैं कि सरकारी गवाह के बयान और साक्ष्य कम से कम इस हद तक पुष्ट होते हैं कि स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति षड्यंत्र के सदस्य थे। सरकारी गवाह ने एक लंबा और विस्तृत बयान दिया है और अदालत में उससे लंबी जिरह की गई। बाबूराम और राम निरंजन ने भी स्वीकारोक्ति करते समय लंबे और विस्तृत बयान दिए। यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन लोगों को बयान देने से पहले एक-दूसरे से परामर्श करने का कोई अवसर नहीं मिला था और संभवतः उन्होंने मिलकर ये बयान गढ़े नहीं होंगे। निष्कर्ष यह है कि ये बयान मुख्यतः सत्य ही होंगे, जब तक कि कोई यह न मान ले कि ये सभी बयान मामले की जाँच कर रहे उप-निरीक्षक या किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा गढ़े गए थे और उमा शंकर और स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्तों के मुँह से निकलवाए गए थे। यह अविश्वसनीय है कि इतने लंबे और जटिल बयान इस तरह गढ़े गए होंगे या यह कि उन लोगों को वे सभी विवरण याद हो सकते थे जिनका उन्होंने उल्लेख किया था। यह कहा गया है कि स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्तों ने पुलिस के कहने पर बयान दिए क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। यह समझना आसान है कि दुर्व्यवहार का शिकार कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार कर सकता है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि अस्थायी दुर्व्यवहार उसे मजिस्ट्रेट के सामने एक लंबी और जटिल कहानी सीखने और दोहराने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। अगर उस पर पुलिस का दबाव होता, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की सुरक्षा लेना बिल्कुल आसान होता और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस स्थिति में कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसा ही करेगा। मैं यह नहीं मान सकता कि पुलिस और मजिस्ट्रेट खुद कई निर्दोष लोगों को फँसाने की साजिश रचेंगे। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, ऐसा करने के पीछे उनका कोई मकसद नहीं होगा। यह सुझाव दिया गया है कि सब-इंस्पेक्टर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा और सराहना पाने की इच्छा से प्रेरित था, लेकिन साक्ष्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके वरिष्ठ अधिकारी, और उस समय राजपत्रित अधिकारी, पूरी जाँच की निगरानी कर रहे थे और उनमें से कुछ ने उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। यह तर्क दिया गया है कि इन वरिष्ठ अधिकारियों को गवाह के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे क्या प्रासंगिक साक्ष्य दे सकते थे। जांच की पूरी प्रक्रिया उपनिरीक्षक द्वारा समझाई गई थी और यदि अभियुक्तगण आवश्यक समझते तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया जा सकता था, या यदि ऐसा प्रतीत होता कि मामले के तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 540 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें बुलाया जा सकता था। यह कहना आसान है कि अभियोजन पक्ष या पुलिस ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत मामला गढ़ा है, लेकिन इस आरोप का क्या अर्थ है, इसकी कल्पना करने की कोई भी कोशिश इस मामले में यही दर्शाएगी कि यह आरोप इतना असंभाव्य है कि अविश्वसनीय

लगता है। हो सकता है कि जिन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया था, वे अभियोजन पक्ष के पक्ष में सबूत पेश करके माफ़ी पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उन्हें कोई खास प्रलोभन दिया गया था या उन्हें छूट का कोई वादा किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय बजरंग को सरकारी गवाह बनाने के सुझाव के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया था, लेकिन उसने बयान देने से इनकार कर दिया। एक अन्य चरण में, राम निरंजन को भी इसी सुझाव के साथ एक मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अदालत में वही बयान नहीं देंगे जो उन्होंने अपने इकबालिया बयान में दिया था। इससे पता चलता है कि एक समय इन लोगों को सरकारी गवाह बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन यह राम निरंजन के इकबालिया बयान के काफी समय बाद हुआ था और इससे यह नहीं पता चलता कि उन्होंने किसी क्षमादान के वादे या किसी प्रलोभन के तहत ऐसा किया था। मैं विद्वान न्यायाधीश से सहमत हूँ कि ये इकबालिया बयान, कम से कम, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य थे, और जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यह मानना असंभव है कि सभी बयान किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गढ़े गए हो सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ये बयान पूरी तरह से सुसंगत नहीं हैं। हो सकता है कि कोई बहुत ही कुटिल पुलिस अधिकारी बयान गढ़ते समय उसे असली दिखाने के लिए उसमें कुछ मामूली विसंगतियां डाल दे, लेकिन इस मामले में विसंगतियां ऐसी नहीं हैं कि उन्हें इस तरह से पेश किया गया हो। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। उमा शंकर ने कहा है कि ढलाईघर में षड्यंत्रकारियों की एक बैठक में इस बात पर काफी चर्चा हुई थी कि स्टेशन पर बम आधी रात को लगाया जाए या रात 9.30 बजे। उमा शंकर के अनुसार, दलपत ने तर्क दिया कि अगर स्टेशन पर भीड़भाड़ वाली ट्रेन होने पर बम लगाया जाए तो बड़ी जनहानि होगी, और बाबू राम, बजरंग और जगदीश ने जवाब दिया कि उस समय बम लगाना फायदेमंद होगा क्योंकि तब सरकार के लिए विस्फोट के बारे में गोपनीयता बनाए रखना संभव नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध में कई लोगों की जान गई थी और अगर किसी नेक काम के लिए कुछ और लोग मारे भी जाएँ तो कोई बात नहीं। राम निरंजन ने भी ढलाईघर की इस घटना का वर्णन किया है, लेकिन बाबूराम ने कहा कि कुली बाज़ार हाउस में बम कहाँ रखे जाएँ, यह जगदीश, शंभू और राम निरंजन ने ही तय किया था। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस तरह की विसंगति उस व्यक्ति द्वारा पैदा नहीं की जा सकती जो अभियुक्तों को प्रशिक्षित कर रहा था, या अभियुक्तों द्वारा विसंगतियाँ पैदा की जा सकती थीं यदि वे दुर्व्यवहार के डर से या पुलिस को साथ लेने के लिए बयान दे रहे थे। मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि बाबूराम बम लगाने के मामले में अपनी संलिप्तता को कम करने की कोशिश कर रहा था, जो अभियुक्त के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप था, और ऐसा करना स्वाभाविक भी था। राम निरंजन निश्चित रूप से अपने दोस्त दलपत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अपने कबूलनामे के अंत में उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया था कि दलपत सिंह डर के मारे छिप रहे थे, उनके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं था और वह बहुत सी बातें नहीं जानते थे, जिससे मुझे लगता है कि उसका मतलब था कि उन्हें साजिश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ये तथ्य बताते हैं कि अभियुक्त पुलिस के हाथों में सिर्फ़ हथियार नहीं थे। विभिन्न बयानों में इन विसंगतियों के बारे में काफी बहस हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विसंगतियाँ इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी के कहने पर बयान नहीं दे रहे थे। इनका कारण आंशिक रूप से यह है कि कुछ अभियुक्त स्वाभाविक रूप से अपना पूरा अपराध स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे और आंशिक रूप से यह तथ्य कि जैसा कि मैं पहले ही देख चुका हूँ, सभी अभियुक्त साजिश के हर पहलू से जुड़े नहीं थे।

इस तरह से चूक का भी हिसाब लगाया जा सकता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वीकारोक्ति कर रहा है, उससे किसी भी संदिग्ध बिंदु के बारे में पूछताछ या जिरह नहीं की जा सकती है ताकि उससे पूरा बयान हासिल किया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि षड्यंत्रकारियों को एक-दूसरे पर कुछ संदेह था, और उनमें से किसी को भी दूसरे क्या कर रहे थे, इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। उनके बयानों से संकेत मिलते हैं कि उन्होंने एक-दूसरे से कुछ राज़ छिपाए थे। बम विस्फोटों के बाद बाबूराम कुछ समय के लिए ग्वालियर चले गए थे और उन्होंने कहा है कि जब वह वापस आएंगे तो अन्य षड्यंत्रकारी उन्हें कोई जानकारी नहीं देंगे या उससे ज्यादा कुछ लेना-देना नहीं रखेंगे। यह तथ्य कि सभी षड्यंत्रकारियों को एक-दूसरे के कार्यों की पूरी जानकारी नहीं थी, कुछ चूकों और विसंगतियों का भी कारण है। जब साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ा जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह षड्यंत्र अस्तित्व में था और खानोल्कर के संभावित अपवाद के साथ आरोपी इसमें शामिल थे। आरोपी और सरकारी गवाह के बयानों के विभिन्न हिस्सों की पुष्टि करने के लिए अन्य गवाहों के साक्ष्य की अच्छी खासी संख्या है। इन गवाहों के साक्ष्य को विस्तार से सुनाना अनावश्यक है। मैंने बजरंग, बाबूराम और राम गुलाम के खिलाफ मामलों

पर विचार करते हुए कुछ गवाहों का उल्लेख किया है। आरोपी पुलिस को विभिन्न दुकानों और कार्यशालाओं में ले गए जहां सामग्री खरीदी गई और काम किया गया। हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि जांच का यह उचित तरीका नहीं था। यह सुझाव दिया गया था कि आरोपियों को पुलिस को विभिन्न स्थानों पर ले जाना नहीं चाहिए था या पुलिस को दुकानों या कार्यशालाओं के मालिकों से उनकी पहचान नहीं करवाना था। वहाँ यह सुझाव दिया गया है कि उचित प्रक्रिया यह होती कि इन लोगों से जेल में परेड के दौरान अभियुक्तों की पहचान करवाई जाती। इस मामले की परिस्थितियों में, मुझे नहीं लगता कि यह आलोचना अमान्य है। एक दुकानदार के लिए जेल जाकर उस व्यक्ति की पहचान करना एक बात होगी जिसने बहुत समय पहले उसकी दुकान से कुछ खरीदा था, और उसके लिए उस व्यक्ति की पहचान करना बिलकुल अलग बात होगी जो दुकान पर आया और कहा कि उसने किसी खास तारीख को या उसके आसपास कुछ खरीदा है, एक ऐसा तथ्य जिसकी पुष्टि दुकान के रिकॉर्ड से की जा सकती है। ऐसे मामले में, जब दुकानदार की याददाश्त इस तरह से जागृत हुई, तो वह इस तथ्य की पुष्टि कर सकता था कि खरीदारी अभियुक्त ने ही की थी। गवाहों की ईमानदारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

विद्वान न्यायाधीश ने इनमें से कुछ गवाहों और सरकारी गवाह के साक्ष्य की आलोचना की है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अनुचित रूप से उच्च मानक स्थापित कर दिए हैं। सरकारी गवाह के बारे में उनकी आलोचना का एक हिस्सा यह है कि उसके बयान असंभाव्य हैं। मैं सभी आलोचनाओं पर चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं रखता। उदाहरण के लिए, सरकारी गवाह के बारे में, वह कहते हैं कि साजिश में उनके शामिल होने की कहानी बहुत संभावित नहीं है। वह व्यक्ति कहता है कि बजरंग ने उसे बताया कि वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था और उसे एक पिस्तौल दिखाई, और बाद में वह एक अवसर पर मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के परिसर से बाहर आते हुए बजरंग से मिला और उसे कुछ छुपाते हुए पाया, जिसके बाद पूछताछ करने पर बजरंग ने उसे बताया कि ब्रह्मानंद के कब्जे में कुछ दोषकारी वस्तुएं हैं और फिर उसे ब्रह्मानंद के घर ले गया और उसे चीजें दिखाईं। विद्वान न्यायाधीश का मानना है कि बजरंग ने सरकारी गवाह को इस तरह से जानकारी नहीं दी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास यह सोचने का अच्छा कारण रहा होगा कि उमा शंकर सहानुभूतिपूर्ण था और उसके द्वारा पुलिस या अधिकारियों को जानकारी देने का कोई खतरा नहीं था। सरकारी गवाह द्वारा बताई गई कहानी का एक हिस्सा यह है कि एक बार बजरंग उसे बाबूराम के घर ले गया, जिसने बाबूराम को कुछ रुई दी, जिसका उपयोग विस्फोटक तैयार करने के लिए किया जाना था और बाबूराम ने सरकारी गवाह को आनंद बाग जाने का निर्देश दिया। सरकारी गवाह का कहना है कि वह उत्सुक हो गया और आनंद बाग गया, जो कुछ फर्लांग की दूरी पर था और वहां उसने बाबूराम को शोम्स डिस्पेंसरी और फिर पिक्रिक हाउस के बारे में बात करते देखा, जिसमें पास की एक गली से प्रवेश किया जा सकता था। विद्वान न्यायाधीश का मानना है कि यह बहुत ही असंभव है कि सरकारी गवाह ने इस तरह से काम किया होगा, लेकिन यह उस व्यक्ति की ओर से जिज्ञासा का एक स्वाभाविक प्रदर्शन था। फिर न्यायाधीश कहते हैं कि यह बहुत ही असंभव है कि सरकारी गवाह द्वारा बताए गए अनुसार ढलाईघर और गांधी पार्क में बैठकें हुई होंगी क्योंकि वे स्थान बहुत सार्वजनिक थे, लेकिन पार्क में पुरुषों के एक समूह के बैठने में कोई असाधारण बात नहीं थी और वे यह देख पा रहे थे कि आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो यह सुन सके कि वे षड्यंत्र से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रहे थे। जहाँ तक ढलाईघर का सवाल है, वे एक कमरे में रहे होंगे और समग्र रूप से प्रस्तुत बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय कानपुर में इस तरह की गतिविधियों के प्रति काफ़ी सहानुभूति थी, और इस बात का कोई डर नहीं था कि कोई खुलासा किया जाएगा। विद्वान न्यायाधीश ने कुछ गवाहों की आलोचना की है जिन्होंने कहा था कि कार्यशालाओं में सामान बनाए गए थे क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने अपने बयानों के समर्थन में जो पुस्तकें प्रस्तुत कीं उनमें जाली प्रविष्टियाँ थीं, लेकिन यह भी कोई अच्छी आलोचना नहीं है क्योंकि हमने पुस्तकों की जाँच की है और वे नियमित लेखा-जोखा की पुस्तकें नहीं हैं जिनका रखरखाव बहुत सटीकता से किया जाता है। अगर ये प्रविष्टियाँ किसी वर्कशॉप के मालिक और कुछ अभियुक्तों के बीच चल रहे दीवानी मुकदमे में पेश की जातीं, तो कुछ प्रविष्टियाँ संदेह का कारण बन सकती थीं, लेकिन अगर कुछ प्रविष्टियाँ आलोचना के दायरे में हैं, तो मामले से बिल्कुल असंबंधित कुछ अन्य प्रविष्टियाँ भी हैं जो उसी तरह की हैं। मेरा मानना है कि ये प्रविष्टियाँ इस मामले के लिए गढ़ी गई थीं। मुझे नहीं लगता कि न्यायाधीश की आलोचनाएँ सही हैं। अपराध स्वीकार करने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के मामलों पर विचार करते समय, हमें यह देखना होगा कि आनंद प्रकाश, हरभगवान और जगदीश को सरकारी गवाह और उन सभी लोगों द्वारा इतना प्रमुख हिस्सा दिया गया था जिन्होंने अपराध स्वीकार किया था कि यह अविश्वसनीय लगता है कि वे इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष थे। वे स्पष्ट रूप से षड्यंत्र के नेता और दिमाग थे। लोख नारायण ने गवाही दी है कि ये तीन व्यक्ति पिक्रिक हाउस आते-जाते थे।

विद्वान न्यायाधीश की आलोचना यह है कि उन्होंने आने-जाने की अवधि और संख्या तय नहीं की है। यह मुझे गवाहों की उचित आलोचना नहीं लगती। उनका (लोख नारायण का) बयान अधिक संदिग्ध हो सकता था यदि यह अधिक निश्चित होता। आनंद प्रकाश के मामले पर चर्चा करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने कहा है कि किसी के साथ जुड़ने से षड्यंत्र में मिलीभगत साबित नहीं होती है। यह, निश्चित रूप से, सच है, लेकिन यह सुझाव नहीं दिया गया है कि केवल जुड़ने से आनंद प्रकाश के खिलाफ मामला स्थापित हो जाएगा। मैं पूरे सम्मान के साथ कह सकता हूँ कि विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्यों को टुकड़ों में बाँटा है और उनके प्रत्येक भाग की अलग-अलग जाँच की है। यह सच हो सकता है कि आनंद प्रकाश या कुछ अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए कोई विशेष साक्ष्य पर्याप्त न हो, लेकिन सभी साक्ष्यों को एक साथ लिया जाना चाहिए, और जब इस तरह से उनकी जाँच की जाती है, तो यह निश्चित रूप से अभियुक्तों की मिलीभगत को स्थापित करता है। जगदीश, राम निरंजन और दलपत की गिरफ्तारी के समय उनके साथ थे, और बाद में जब उन्हें स्वयं गिरफ्तार किया गया, तो उनके पास एक रिवॉल्वर पाई गई। उनका यह स्पष्टीकरण कि वह सरजू और तपेश्वर के घर इसलिए गए थे क्योंकि वह देर रात सिनेमा देखने गए थे और घर नहीं जाना चाहते थे, बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने उन घरों में से एक की चाबी पेश की, जिसे षड्यंत्रकारियों ने पट्टे पर लिया था। लोख नारायण ने गवाही दी है कि हरभगवान बाबूराम के साथ थे जब उन्होंने शोम से मकान किराए पर लिया था और डॉ. गंगा प्रसाद ने भी अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ उसके संबंध का सबूत दिया है। डॉ. गंगा प्रसाद ने यह भी गवाही दी है कि इस व्यक्ति ने उनसे कार्बोलिक एसिड और मेडिकल कॉटन खरीदा था, और आरोपी ने यह नहीं बताया है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस तरह के स्पष्टीकरण के अभाव में मुझे विद्वान न्यायाधीश के इस तर्क में कोई बल नहीं दिखता कि ये सामान्य उपयोग की वस्तुएं हैं और खरीद के तथ्य से आरोपी के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। चावला का नाम स्वीकारोक्ति और सरकारी गवाह के साक्ष्य में था और डॉ. गंगा प्रसाद और राम चरण नामक एक व्यक्ति ने षड्यंत्रकारियों के साथ उसके संबंध का सबूत दिया है। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि इन गवाहों को इस आदमी के खिलाफ झूठी गवाही देनी चाहिए। शंभू का नाम भी स्वीकारोक्ति और सरकारी गवाह के बयान में है।

हालाँकि उसकी मिलीभगत के बारे में अन्य बयान मौजूद हैं और राम निरंजन ने कहा है कि वह बम विस्फोट के बाद ही षडयंत्र में शामिल हुए थे, फिर भी तथ्य यह है कि सरकारी गवाह और स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्त का कहना है कि वह षडयंत्र का सदस्य थे और निस्संदेह उन्हें जगदीश के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। उनका यह स्पष्टीकरण कि वह तपेश्वर के नियोक्ता से कपड़ा खरीदने के लिए ही कानपुर गए थे, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। उनके पास कोई पैसा नहीं था, और उन्होंने किसी भी फर्म या अपने व्यवसाय का कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चले कि वह किसी निर्दोष उद्देश्य से कानपुर गए थे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके खिलाफ सबूत पर्याप्त हैं। दलपत सिंह का नाम भी इकबालिया बयानों और सरकारी गवाहों द्वारा लिया गया है और उन्हें राम निरंजन के साथ गिरफ्तार किया गया था। प्रभाकर को ढलाईघर से गिरफ्तार किया गया और उन्होंने साजिश से जुड़े कई घरों की ओर इशारा किया। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने और दलपत सिंह ने इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे साजिश से वाकिफ थे और उन लोगों में शामिल थे जो इस बात पर सहमत थे कि ये विध्वंसक गतिविधियाँ की जानी चाहिए।

यह याद रखना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें जूरी ने सर्वसम्मति से सभी अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम के नियम 38 और धारा 19 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया था। यह निश्चित रूप से सत्य है कि अभियुक्त के अपराध का पूरा प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के प्रावधानों के तहत हमारे सामने खुला है, लेकिन हमें जूरी के निष्कर्ष की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें इसमें तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब हम संतुष्ट हों कि यह अनुचित है। मुझे स्वयं इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि मैं जूरी का सदस्य होता, तो मैं खानोल्कर को छोड़कर, अभियुक्तों के अपराध के बारे में अन्य सभी से सहमत होता। मेरे विचार से, कुल मिलाकर साक्ष्य पूरी तरह से निर्णायक हैं। खानोल्कर का मामला कुछ हद तक अन्य मामलों से अलग है क्योंकि सरकारी गवाह और अपराध स्वीकार करने वाले अभियुक्तों के बयानों में भी उनके खिलाफ बहुत कम सबूत हैं। किसी भी अपराध स्वीकार करने वाले अभियुक्त ने उनका नाम नहीं लिया। सरकारी गवाह ने उनका नाम ज़रूर लिया, लेकिन उन्हें साजिश में बहुत कम भूमिका दी। जहाँ तक जूरी का सवाल है, हो सकता है कि उन्होंने उनके मामले को अन्य मामलों से पर्याप्त रूप से अलग नहीं किया हो, और इसलिए मैं यह मानूँगा कि वह दोषी नहीं थे और उन्हें बरी कर दूँगा।

सवाल यह है कि बाकी आरोपियों ने क्या अपराध किए थे। आनंद प्रकाश, हरभगवान और चावला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं, और आनंद प्रकाश पर भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 19 और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। सौभाग्य से, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या भारतीय दंड संहिता की धारा 435 के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। एक बार जब यह मान लिया जाता है कि वे बम बनाने की साजिश के सदस्य थे और बम बनाए गए थे, जैसा कि निस्संदेह था, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि वे साजिश के दोषी थे और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के साथ-साथ भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 के तहत अपराध के भी दोषी थे। सरकारी गवाह और अपराध स्वीकार करने वाले अभियुक्तों के इस कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि आनंद प्रकाश ने ही हथियार और बम बनाने के लिए ढलाईघर खोलने की व्यवस्था की थी। इसलिए वह भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 19 सपठित धारा 109 के प्रावधानों के तहत भी दोषी होंगे। यद्यपि यह प्रश्न शैक्षणिक महत्व का है, क्योंकि विभिन्न अपराधों के लिए उन पर लगातार सजा पारित करना अनावश्यक है। जगदीश प्रसाद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 302 और 435 के तहत अपराधों के साथ-साथ भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 (ए), 6 और 3 के तहत अपराधों और शस्त्र अधिनियम की धारा 19 और भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को छोड़कर इन सभी धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। उन्हें उस धारा के तहत एक अपराध से बरी कर दिया गया है। विद्वान न्यायाधीश इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि सरकारी गवाह और स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्त के इस तथ्य की कोई विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई कि यह व्यक्ति बम को रेलवे स्टेशन ले जाने में शामिल था। मैं इस तर्क से ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। राम निरंजन, बाबूराम और उमा शंकर सभी इस बात पर सहमत हैं कि जगदीश इस मामले में शामिल थे। बाबूराम का कहना है कि वह विशेष बम कुली बाज़ार हाउस से किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया था। राम निरंजन ने कहा है कि वह जगदीश से ढलाईघर में मिले थे और वे वहाँ से बम लेने के लिए सरजू के घर गए थे। सरजू ने इस कथन का समर्थन किया है। विद्वान न्यायाधीश ने सरजू के बयान पर भरोसा नहीं किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह एक सहयोगी थे। यह संदेह करने का निश्चित कारण है कि सरजू इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ नहीं थे। अभियुक्त जगदीश और शंभू को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें और उनके बेटे तपेश्वर को भी उसी समय गिरफ्तार किया गया था, हालाँकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन केवल यह अनुमान कि सरजू एक सहयोगी थे, इस प्रश्न को जन्म देता है कि वह किसके सहयोगी थे? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बम किसी ने थाने तक पहुँचाया था। यह समझ में नहीं आता कि अगर षड्यंत्र के किसी अन्य सदस्य ने ऐसा किया था, तो राम निरंजन ने इसे लेने की बात क्यों स्वीकार की होगी, और कोई कारण नहीं था कि पुलिस ने राम निरंजन को षड्यंत्र के इस विवरण को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया होता। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उनके मन में उसके प्रति कोई विशेष भावना थी, या यह मानने का कि वे चाहते थे कि वह उन्हें मामले के वास्तविक तथ्यों के अलावा कुछ और बताए। यह भी समझ नहीं आता कि अगर जगदीश ने बम को थाने ले जाने में मदद नहीं की थी, तो राम निरंजन ने यह काम जगदीश को क्यों सौंपा। फिर हमारे पास अन्य स्वीकारोक्ति करने वाले गवाहों की स्वतंत्र कहानियाँ भी हैं। यहाँ भी, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पुलिस सच्चाई का पता नहीं लगाना चाहती थी, या उनके पास अन्य षड्यंत्रकारियों के बजाय जगदीश पर अतिरिक्त दोष मढ़ने की कोई विशेष इच्छा थी। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि अगर जगदीश बम को पुलिस स्टेशन नहीं ले गए होते, तो उन्हें षडयंत्र में यह भूमिका सौंपने के पीछे किसी का कोई मकसद था। सरजू भी जगदीश का किसी भी तरह से विरोधी नहीं थे। उन्होंने स्वीकार किया कि बम उनके घर लाया गया और ले जाया गया। कुली बाजार हाउस के भूतल पर बालमकुंद नाम का एक बढ़ई रहता था। उसने कहा कि उसने जगदीश को बम ले जाते देखा था। उसने लकड़ी का बक्सा बनाया था जिसमें बम रखा गया था। विद्वान न्यायाधीश को उसके बयान पर संदेह है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। विद्वान न्यायाधीश का कहना है कि वह यह सब नहीं देख पाए होंगे क्योंकि उसने स्वीकार किया कि उस समय उसके पास किसी भी संदेह का कोई कारण नहीं था। यह तर्क यह मानता है कि जब उस व्यक्ति ने कहा कि उसे कोई संदेह नहीं है, तो वह सच बोल रहा था। यह केवल आत्म-मुक्ति का बयान था। मुझे लगता है कि उसके पास कार्यवाही में रुचि रखने और उस शाम विस्फोट होने की जानकारी मिलने पर उसे कार्यवाही याद रखने के सभी कारण थे। मेरे विचार से, साक्ष्यों का पूरा भार ऐसा है कि यह मानना असंभव है कि जगदीश षडयंत्र के इस हिस्से में निर्दोष थे। जगदीश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के प्रावधानों के तहत अपने खिलाफ सबूतों को स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था और

मुझे शायद उस धारा की दूसरी उपधारा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो कहती है:-

"अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करके या उनके झूठे उत्तर देकर स्वयं को दण्ड का भागी नहीं बनाएगा, किन्तु न्यायालय और जूरी, यदि कोई हो, ऐसे इंकार या उत्तरों से ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसा वह उचित समझे।"

विद्वान न्यायाधीश ने, मेरी राय में, सही माना है कि जगदीश ने इस षड्यंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और जगदीश ने यह सुझाव नहीं दिया है कि, हालांकि बाकी सबूत सच हो सकते हैं, वह बम को रेलवे स्टेशन नहीं ले गए थे, न ही उन्होंने संकेत दिया कि इसे कौन ले गया, एक तथ्य जिसे वह अवश्य जानते होंगे। इन परिस्थितियों में, मुझे उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है और मैं समझता हूं कि वह निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे। शंभू दयाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और भारतीय दंड संहिता की धारा 435 और 302 सपठित संहिता की धारा 109 के तहत आरोप लगाए गए थे। उन पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 (ए) और 6 और भारत की रक्षा नियमावली के नियम 38 और 39 के तहत अपराध का भी आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश का मानना नहीं है कि वह किसी भी अपराध के दोषी थे। मुझे जूरी के निष्कर्षों से मतभेद का कोई कारण नहीं दिखता कि वह भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 और 39 के तहत दोषी थे। जूरी ने पाया है कि उनके कब्जे से कुछ राजद्रोहपूर्ण वस्तुएं पायी गयी थीं, और यह मानने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उनका निष्कर्ष अनुचित है। जिन कारणों को मैंने पहले ही दिया है, उनके लिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि वह धारा 120 बी के तहत अपराध के भी दोषी थे और यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि वह भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 (ए) और 6 के तहत अपराधों के भी दोषी थे। चूंकि वह बम बनाने की साजिश का सदस्य थे और उन्हें पता होना चाहिए कि उनका इस्तेमाल किया जाना था, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 435 के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए भी दोषी होंगे। हालांकि, यह आवश्यक रूप से अनुसरण नहीं करता है कि वह इस बात से सहमत थे कि बम का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे मौत हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इस व्यक्ति की साज़िश में भागीदारी के बारे में बयानों में कुछ विसंगति है। वह निश्चित रूप से प्रमुख व्यक्तियों में से एक नहीं थे। बाबूराम ने कहा है कि वह उन लोगों में से एक थे जिन्होंने तय किया कि बम कहाँ रखे जाने चाहिए, लेकिन यह बयान निर्णायक नहीं है, खासकर जब बाबूराम स्पष्ट रूप से इस मामले में अपनी संलिप्तता कम करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे संदेह है कि क्या यह स्थापित हो पाया है कि शंभू दयाल वास्तव में दूसरों के साथ इस बात पर सहमत थे कि बम ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर लगाए जाने चाहिए जिससे मृत्यु होने की पूरी संभावना हो, और इसलिए मैं उन्हें धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत दोषी नहीं ठहराता हूँ। बजरंग सिंह को उन सभी अपराधों का दोषी पाया गया है जो आरोप के अधीन हैं, सिवाय नियम 39 के तहत एक अपराध के, जिसका उन पर आरोप नहीं लगाया गया था। विद्वान न्यायाधीश जूरी से असहमत हैं, जिसने उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत एक अपराध का दोषी माना था। मुझे जूरी से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। इस बात के प्रमाण हैं कि इस व्यक्ति के पास रिवॉल्वर थे और वह रिवॉल्वर बनाने का प्रयास कर रहा था। मैं इस स्तर पर कह सकता हूँ कि यह प्रश्न भी उठता है कि क्या बजरंग सिंह की मृत्युदंड की सज़ा बरकरार रखी जानी चाहिए। यह सच है कि इस षडयंत्र के कारण रेलवे स्टेशन पर गंभीर अपराध हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, लेकिन दूसरी ओर, अपराध को हुए काफी समय हो गया है और मुझे संदेह है कि बजरंग सिंह षडयंत्र के नेताओं में से एक (अपठनीय) थे। निस्संदेह, उन्होंने बहुत सक्रिय भाग लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि षडयंत्र का संगठन किसी और के हाथ में था और यह व्यक्ति वास्तव में षडयंत्र के साधनों में से एक था। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें उन अन्य लोगों की तुलना में अधिक कठोर सजा मिले जो संभवतः अधिक दोषी थे। इसलिए मैं मृत्युदंड को रद्द कर उसे आजीवन निर्वासन में बदलता हूँ। बाबूराम पर भी बजरंग के समान धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया है और परिणाम भी वही रहे हैं। मेरे विचार में, उनके बारे में भी वही कहा जा सकता है जो बजरंग के बारे में कहा गया है और उन्हें भी वही सज़ा सुनाई जानी चाहिए। राम निरंजन पर भी उन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया है, सिवाय इसके कि उन पर धारा 302 सपठित धारा 109 के बजाय धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया है। मुझे लगता है कि उनके इस कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि वह वास्तव में बम को रेलवे स्टेशन पर इस इरादे से ले जाया गया था कि जब कोई भीड़-भाड़ वाली ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पर हो, तो उसे विस्फोट कर दिया जाए, और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। उनके मामले में यह सवाल उठता है कि क्या सज़ा को बढ़ाकर मौत की सज़ा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन बजरंग सिंह

और बाबूराम के मामलों पर लागू होने वाले लगभग उन्हीं कारणों से, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। दलपत सिंह और परमेश्वरी पर एक जैसे आरोपों के तहत मुकदमा चलाया गया है, अर्थात, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, धारा 302 सपठित धारा 109 और धारा 435 सपठित धारा 109, भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत अपराध और भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 के तहत अपराध के लिए। इन दोनों व्यक्तियों के मामले कुछ हद तक बचाव पक्ष के समान हैं। स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों में उन्हें कोई प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। इस बात के प्रमाण हैं कि दलपत कई बार उन घरों में रहे थे जो षड्यंत्रकारियों द्वारा कब्जे में लिए गए थे, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, उन्हें राम निरंजन के साथ गिरफ्तार किया गया था। बयानों में कहा गया है कि उन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया था, लेकिन उनके खिलाफ सरकारी गवाह का लगाया गया एकमात्र गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने बम को रेलवे स्टेशन ले जाने की पेशकश की थी। इसके अलावा, उन्होंने निश्चित रूप से अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ सांठगांठ की थी और कहा जाता है कि उन्होंने विस्फोटक बनाने के लिए गंधक पीसकर मदद की थी। सभी साक्ष्यों को देखते हुए, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सरकारी गवाह के इस कथन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं कि वह बम को स्वयं रेलवे स्टेशन ले जाने को तैयार थे। इसलिए, मेरा मानना है कि यह सिद्ध नहीं होता कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 109 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का दोषी थे। परमेश्वरी का उल्लेख केवल सरकारी गवाह और राम निरंजन ने ही किया था। उन दोनों ने कहा कि जब यह तय हो गया था कि एक और ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उन्होंने 14 अप्रैल को दूसरा बड़ा बम ले जाकर कोतवाली में लगाने की पेशकश की थी, लेकिन योजना छोड़ दी गई; और मुझे संदेह है कि क्या ये दोनों बयान अपने आप में इस निष्कर्ष को सही ठहराएँगे कि उस आदमी ने किसी की हत्या की साजिश रची थी। रेलवे स्टेशन पर बम लगाने से उसका कोई संबंध नहीं है। वह निश्चित रूप से जगदीश के साथ मोंढा टोली वाले घर में रहते थे और उसे भी ढलाईघर के दरवाजे पर गिरफ्तार किया गया था और पुलिस उसे सीसमऊ स्टोर हाउस ले गई जहाँ से खोखे बरामद किए गए थे। इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बम बनाने की साजिश में शामिल थे। इसका यह मतलब नहीं कि वह कभी इस बात पर सहमत थे कि बमों का इस्तेमाल खतरनाक तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इन दोनों लोगों को धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत अपराध से बरी करता हूँ और बाकी धाराओं के तहत उन्हें दोषी ठहराता हूँ। राम गुलाम और शोम के बारे में मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे शुरू में साजिश में शामिल थे, लेकिन वे कभी भी कोई सक्रिय हिस्सा लेने के लिए उत्सुक नहीं थे और कुछ हद तक डरपोक और झिझकते थे। वे निस्संदेह बम बनाने की साजिश के बारे में जानते थे, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम गुलाम ने इस उद्देश्य के लिए सामग्री जुटाई थी, लेकिन इसके अलावा, मुझे लगता है कि उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर अन्य षड्यंत्रकारियों को रहने की जगह देकर और खतरनाक सामान रखकर उनकी मदद की। यह मानने का कोई वास्तविक कारण नहीं है कि वे वास्तव में अन्य षड्यंत्रकारियों से सहमत थे कि बम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर लगाए जाने चाहिए जहाँ विस्फोट से मौत हो सकती है। उन पर दलपत सिंह और परमेश्वरी के समान आरोपों पर मुकदमा चलाया गया है। मैं उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत अपराध से बरी करता हूँ और अन्य धाराओं के तहत उन्हें दोषी ठहराता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्हें दूसरों जितनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शोम पहले ही काफी समय से जेल में है, और मुझे लगता है कि उन्हें जो सज़ा मिली है, वह उसके लिए पर्याप्त है। मैं राम गुलाम को कुल तीन साल के कठोर कारावास की सज़ा दूँगा। मेरे निष्कर्ष का नतीजा यह है कि खानोल्कर को उन सभी आरोपों से बरी कर दिया जाना चाहिए जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं, और अगर वह जेल में है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में रखना ज़रूरी न हो। मैं आनंद प्रकाश, हरभगवान और जी.डी. चावला को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराता हूँ और प्रत्येक धारा के तहत उन्हें सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। मैं उन्हें भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 के तहत अपराधों का भी दोषी पाता हूँ और उन नियमों के तहत उनमें से प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। मैं आनंद प्रकाश को शस्त्र अधिनियम की धारा 19 और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अंतर्गत भी दोषी पाता हूँ और उन्हें इसी धारा के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। सभी सजाएँ एक साथ चलनी चाहिए।

मैं निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश द्वारा जगदीश प्रसाद को सुनाई गई सज़ा को बरकरार रखता हूँ और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी पाता हूँ और उसी धारा के तहत उन्हें आजीवन निर्वासन की सज़ा सुनाता हूँ। ये सज़ाएँ साथ-साथ चलनी चाहिए।

मैं शंभू दयाल, दलपत सिंह और परमेश्वरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 435/109 और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत अपराधों का दोषी पाता हूँ और उन्हें प्रत्येक धारा के तहत सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। मैं उन्हें भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 के तहत भी अपराध का दोषी पाता हूँ और उन्हें उस नियम के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। और मैं शंभू दयाल को भारत रक्षा नियमावली के नियम 139 के अंतर्गत एक अपराध का दोषी पाता हूँ और उसी नियम के अंतर्गत उन्हें तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। मैं अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 109 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से बरी करता हूँ; और अभियुक्त को सुनाई गई सजाएँ साथ- साथ चलनी चाहिए।

मैं बजरंग सिंह और बाबूराम की दोषसिद्धि और निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा की पुष्टि करता हूँ, सिवाय इसके कि मैं धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत मृत्युदंड को आजीवन निर्वासन की सजा में बदलता हूँ। मैं दोनों अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराधों का दोषी पाता हूँ और उनमें से प्रत्येक को उस धारा के तहत तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाता हूँ। कारावास की सजाएँ अन्य सजाओं के साथ-साथ चलनी चाहिए।

मैं राम निरंजन की दोषसिद्धि और निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश द्वारा उन्हें सुनाई गई सजाओं की पुष्टि करता हूँ।

मैं राम गुलाम और शोम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत अपराधों से बरी करता हूँ, लेकिन अन्य धाराओं के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि करता हूँ। मैं प्रत्येक धारा के तहत राम गुलाम को दी गई कारावास की सजा को घटाकर तीन वर्ष करता हूँ।

सभी सज़ाएँ साथ-साथ चलनी चाहिए। मैं शोम को दी गई सज़ाओं को प्रत्येक धारा के तहत पहले से काटी गई कारावास की अवधि तक कम करता हूँ और निर्देश देता हूँ कि उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले में उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक न हो।

माननीय मुख्य न्यायाधीश
मैं माननीय न्यायाधीश ऐलसोप (Allsop) द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हूँ।
न्यायालय द्वारा

हम आनंद प्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4(ए) और 6, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 19 सपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 के तहत अपराध का दोषी पाते हैं। हम उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत सात साल के कठोर कारावास और भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 19 सपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं। ये सजाएँ एक साथ चलेंगी।

हम राम निरंजन की दोषसिद्धि और अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा की पुष्टि करते हैं।

हम राम गुलाम और शोम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत अपराधों से बरी करते हैं, लेकिन हम अन्य धाराओं के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं। हम राम गुलाम को सुनाई गई कारावास की सजा को प्रत्येक धारा के तहत तीन वर्ष की अवधि तक कम करते हैं। ये सजाएँ एक साथ चलनी चाहिए। हम शोम को सुनाई गई सजा को प्रत्येक धारा के तहत पहले से काटी गई कारावास की अवधि तक कम करते हैं और निर्देश देते हैं कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक न हो।

हम निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश द्वारा जगदीश प्रसाद को सुनाई गई सज़ा को बरकरार रखते हैं और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी पाते हुए उसी धारा के तहत आजीवन निर्वासन की सज़ा सुनाते हैं। ये सज़ाएँ साथ- साथ चलेंगी।

हम शंभू दयाल, दलपत सिंह और परमेश्वरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 435/109 और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी पाते हैं और उन्हें प्रत्येक धारा के तहत सात-सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं। हम उन्हें भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 के तहत अपराध का भी दोषी पाते हैं और उन्हें उस नियम के तहत तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं, और हम शंभू दयाल को भारत रक्षा नियमावली के नियम 39 के तहत अपराध का भी दोषी पाते हैं और उन्हें उस नियम के तहत तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं। हम आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत दंडनीय अपराध से बरी करते हैं।

हम बजरंग सिंह और बाबूराम की दोषसिद्धि और उन्हें निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सज़ा की पुष्टि करते हैं, सिवाय इसके कि हम धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत मृत्युदंड को आजीवन निर्वासन की सज़ा में बदलते हैं। इसके अलावा, हम दोनों अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराधों का दोषी पाते हैं और उनमें से प्रत्येक को उस धारा के तहत तीन वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाते हैं। ये सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी।

हम हरभगवान और जी.डी. चावला को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और विस्फोटक अधिनियम की धारा 4(ए) और 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं और प्रत्येक धारा के तहत उन्हें सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं। हम उन्हें भारत रक्षा नियमावली के नियम 38 सपठित नियम 121 के तहत अपराधों का भी दोषी पाते हैं और उन नियमों के तहत उनमें से प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं। ये सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी।

हम खानोल्कर को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी करते हैं और निर्देश देते हैं कि वर्तमान मामले में उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले में उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक न हो। आनंद प्रकाश, हरभगवान, चावला, शंभू दयाल, दलपत और परमेश्वरी अपनी-अपनी सज़ाएँ पूरी करने के लिए आत्मसमर्पण करेंगे।

(एससीए)
दिनांक: 15.3.1946

आभार अभिव्यक्ति

परम सम्मान के साथ, हम माननीय **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन कमेटी**, उच्चतम न्यायालय का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से न्यायिक निर्णयों को आम जनमानस की भाषा में उपलब्ध कराया जा सका।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** के तत्वावधान में सुवास प्रकोष्ठ द्वारा **"ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" एवं त्रैमासिक ई-पत्रिका "न्यायाभा - न्याय की किरण"** के प्रकाशन के साथ ही **"ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय"** का प्रकाशन किया जा रहा है। यह कड़ी न्यायिक एवं विधिक ज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन बन रही है।

इस ई-पुस्तिका के प्रथम संस्करण में ऐतिहासिक **मुक़दमा चौरी चौरा**, द्वितीय संस्करण में **केशव सिंह प्रकरण** एवं तृतीय संस्करण में **आगरा षड्यंत्र केस** का प्रकाशन किया गया तथा यह चतुर्थ संस्करण स्वतंत्रता पूर्व ऐतिहासिक **कानपुर बम विस्फोट प्रकरण** को समर्पित है।

इस अवसर पर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति **श्री अरुण भंसाली जी** का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है। **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति **श्री अजित कुमार जी,** जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों की पुस्तिका के प्रकाशन का विचार प्रस्तुत किया और संपादक मंडल का कुशल नेतृत्व किया एवं समिति के सदस्यगण माननीय न्यायमूर्ति **श्री समीर जैन जी,** माननीय न्यायमूर्ति **श्री विक्रम डी. चौहान** जी एवं माननीय न्यायमूर्ति **श्री विवेक कुमार सिंह** जी का हृदय से धन्यवाद, जिनके दिशा-निर्देशन में यह प्रकाशन साकार हो रहा है। **श्री मंजीत सिंह श्योराण,** विद्वान महानिबंधक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रकाशन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

इस प्रकाशन को साकार बनाने और उनके अमूल्य योगदान के लिए, हम माननीय कमेटी के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण के निजी सचिवगण तथा सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करने के साथ ही आशा करते हैं कि यह प्रकाशन न्यायिक ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

संपादक मण्डल

सुवास प्रकोष्ठ की संरचना

संयुक्त निबंधक
श्री विवेक श्रीवास्तव

सहायक निबंधक
श्री गोपाल सिंह बिष्ट (लखनऊ)

अनुभाग अधिकारी
सर्वश्री डॉ० मो. शहाब सिद्दीकी, सुधीर तिवारी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार कुशवाहा, राजेश तिवारी (लखनऊ)

समीक्षा अधिकारी
सर्वश्री राधा रमन, डॉ० अनुपम श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, अमित कुमार पांडे, सुश्री प्रियंका गौतम, सुश्री आकृति मिश्रा, श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी, श्री धरिन्द्र प्रताप, श्री मनीष कुमार सिंह, सुश्री शालिनी सिंह, श्रीमती अंजलि कुशवाहा

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
सर्वश्री प्रियरंजन, कुलदीप निगम, आदित्य मिश्रा, सुश्री अक्षिता चौधरी, सर्वेश कुमार वर्मा, शुभम पांडे, शुभम गुप्ता, सूरज गोस्वामी, सैयद असीम रसीद, जय शंकर यादव, प्रदीप कौशल, सुश्री अंकिता सचान, आशुतोष कुमार (लखनऊ), गजेन्द्र प्रताप सिंह (लखनऊ), श्रीमती काव्या यादव (लखनऊ), जितेंद्र कुमार (लखनऊ)

निर्णय अनुवादक (संविदा कर्मी)
सर्वश्री मनीष पाण्डेय, दिलीप शुक्ला, मनीष मिश्रा, उमेश शुक्ला

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
श्री राकेश कुमार

संपादक मण्डल

वरिष्ठ संपादक

श्री विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री विनय सरन, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री समीर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

संपादक मण्डल

श्री अजय चंद्र गुप्ता
श्री अनिल मिश्र
श्री आशीष सिंह
श्री अनिल गुप्ता
श्री आशीष कुमार
श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव
सुश्री अर्चना सिंह
श्री आशुतोष कुमार राय
श्री ईश शरन
सुश्री गौरी दूबे
श्री कार्तिकेय सिंह
श्री कुणाल शाह
सुश्री निधि वर्मा
श्री पंकज कुमार अस्थाना
सुश्री साधना सिंह
श्री श्रेयस श्रीवास्तव
सुश्री सिमरन यादव
सुश्री सोनाक्षी अरोरा
श्री विनायक वर्मा
श्री यावर मुख्तार

पदेन सदस्य

डॉ अनिल कुमार सिंह - II (उ.न्या.सेवा / समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)-समन्वयक-संपादक मण्डल
श्री विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त-निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
डॉ. अनुपम श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री मनीष कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

न्यायाभा
न्याय की किरण

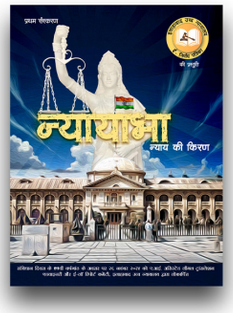

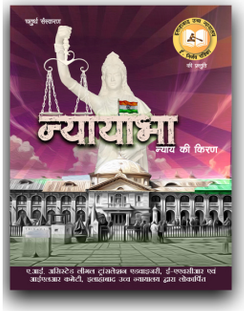

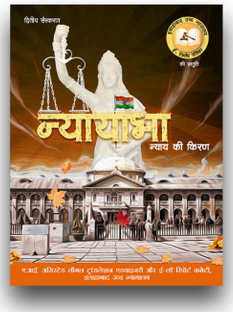

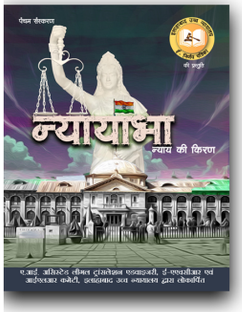

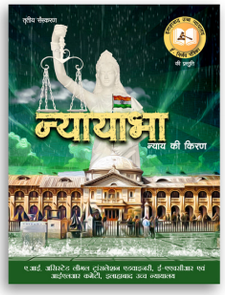

ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

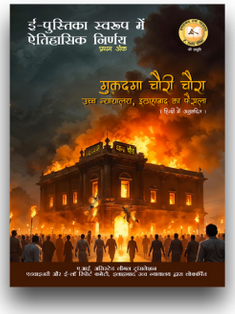

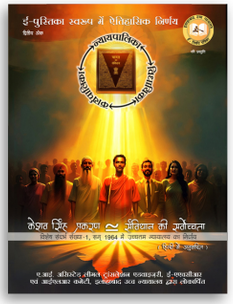

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं
आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय